नई दिल्ली ■ मंगलवार 31 मार्च 2026 ■ मूल्य 5.00 ■ वर्ष 14 ■ अंक 02 ■ पृष्ठ 08

JBT जनभावना टाइम्स
www.thejbt.com
निष्पक्ष और निर्भीक खबर
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल एवं करनाल से प्रकाशित

04 भारत-अमेरिका व्यापार समझौता | 07 हॉकी इंडिया ने की 31 सदस्यीय सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की घोषणा | 40 की उम्र में दूसरी बार मां बनीं सोनम कपूर 08

प्रधानमंत्री का असम के भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद

घुसपैठ केवल चुनावी मुद्दा नहीं, अस्मिता की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय : मोदी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को असम के भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के माध्यम से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा-एनडीए की हैट्रिक जीत के लिए कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने की अपील की।

उन्होंने विपक्षी दलों पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा असम की अस्मिता, सुरक्षा और संस्कृति से सीधे जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को नमो ऐप के जरिए 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' कार्यक्रम के तहत राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी दायित्व सौंपती है, उसे निभाने के लिए वे पूरी ताकत लगाते हैं। असम में भाजपा-एनडीए की हैट्रिक लगे, इसके लिए राज्य के पार्टी कार्यकर्ता जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बोहाग बिहू और अन्य त्योहारों की तैयारियों के बीच चुनावी अभियान चलाने वाले कार्यकर्ताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि असम ने लंबे समय तक अस्थिरता, हिंसा और उग्रवाद का दौर देखा था, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार ने शांति, विकास और सुरक्षा का नया दौर शुरू किया है। पिछले 10 वर्षों में 12 बड़े शांति समझौते हुए हैं जो असम की नई तस्वीर बनाते हैं। संवाद के दौरान विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए।

सुनितपुर जिले के पंकज हजारी ने कहा कि साल 2016 से पहले असम में अराजकता और उग्रवाद चरम पर था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद किसानों, व्यवसायियों और शिक्षकों के जीवन में अमूल्य परिवर्तन आया है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 18-22 साल के युवा मतदाता केवल पिछले 10 साल की शांति को जानते हैं, इसलिए बूथ कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि उन्हें पुराने दिनों की हिंसा और कांग्रेस की नीतियों की याद दिलाएं। भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर भजन संध्या, विरासत उत्सव और योजनाओं पर चर्चा के कार्यक्रम आयोजित करें ताकि नई पीढ़ी पुरानी गलतियों को दोहराने से बचे। तामलपुर जिले के धनेश्वर ने बोडोलैंड समझौते के बाद आए बदलाव को विस्तार से बताया।

उन्होंने बताया कि वह पार्टी कार्यकर्ता होने के साथ साथ वे व्यवसायी भी हैं। और राज्य के लोगों को पुरानी सरकार की कुरीतियों के बारे में बताते भी हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बोडोलैंड आज पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बन गया है, जहां पहले कर्फ्यू और धमाके होते थे, आज शांति और सांस्कृतिक धुनें गूंज रही हैं।

उन्होंने कहा कि बंदूक छोड़कर कलम थामने वाले पूर्व उग्रवादियों और उनकी माताओं के अनुभव साझा करने के कार्यक्रम बूथ स्तर पर आयोजित करें। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की सूची बनाएं और उन्हें टोली बनाकर वोट डालने के लिए प्रेरित करें। नौगांव जिले की दीपी दास ने कहा कि वह पिछले 9 साल से भाजपा के साथ लोगों की सेवा के लिए जुड़ी हुई हैं।

पुडुचेरी की जनता कांग्रेस-द्रमुक को सत्ता में आने का मौका नहीं देगी : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पुडुचेरी की जनता कांग्रेस और द्रमुक को केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता में आने नहीं देगी क्योंकि दोनों दल जनहित के बजाय 'परिवार पहले' रखने के सिद्धांत पर खड़े हैं। मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के बूथ-स्तरीय कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग)'पुडुचेरी पहले, भारत पहले' का प्रतिनिधित्व करता है और पार्टी कार्यकर्ताओं से इस संदेश को हर युवा तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक)के 'कुकृत्यों' के प्रति जनता के असंतोष को 'प्रभावी ढंग से उजागर करने' के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की सराहना की। मोदी ने भाजपा की 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत संवाद' पहल के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके (कांग्रेस-द्रमुक)के बीच जारी संघर्षों के बावजूद उनका व्यवहार नहीं बदला है। वे भली-भांति जानते हैं कि पुडुचेरी की जनता उन्हें दूसरा मौका नहीं देगी। भाजपा का 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत संवाद' चुनावी राज्यों के कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ने की पहल है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और द्रमुक इस उम्मीद में आपस में लड़ना जारी रखे हुए हैं कि अगर कोई मौका मिला तो वे लाभ का बड़ा हिस्सा हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि आज मैं सभी पार्टी सदस्यों को एक ही काम सौंपना चाहता हूं। घर-घर जाकर, हर नागरिक से मिलें और उन्हें स्पष्ट रूप से बताएं कि कांग्रेस-द्रमुक का अभिप्राय परिवार सर्वोपरि है जबकि भाजपा-राजग का मतलब पुडुचेरी सर्वोपरि, भारत सर्वोपरि है। यह बात हर युवा तक पहुंचनी चाहिए।

लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी शब्बीर अहमद लोन गिरफ्तार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक दुर्दान्त आतंकवादी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, लोन इस पूरे मॉड्यूल का हैंडलर था और हाल ही में सामने आए मेट्रो पोस्टर मामले में पकड़े गए आतंकी नेटवर्क को संचालित कर रहा था।

स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्पेशल सेल की नई दिल्ली रेंज के पुलिस उपायुक्त प्रवीण त्रिपाठी की देखरेख मे आतंकी को रविवार देर रात गाजीपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बताया कि शब्बीर अहमद लोन के कब्जे से करीब 2,300 बांग्लादेशी टका, 3,000 से 5,000 पाकिस्तानी मुद्रा (लगभग 3,000 भारतीय रुपये के बराबर) और एक नेपाली सिम कार्ड मिला है। इन सभी सामानों को जब्त कर लिया गया है और उनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। जांच से यह भी सामने आया है कि लोन लंबे समय से बांग्लादेश में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। इससे पहले उसने हटियारा (कोलकाता) में अपने मॉड्यूल के लिए एक ठिकाना तैयार किया था, जो उसके सहयोगियों के लिए 'सेफ हाउस' के तौर पर इस्तेमाल होता था।

स्पेशल सेल के अधिकारी के मुताबिक, यह ठिकाना आतंकी गतिविधियों के संचालन और सदस्यों के छिपने के लिए बेहद अहम था। यहीं से मॉड्यूल के सदस्यों को निर्देश दिए जाते थे और आगे की साजिशें रची जाती थीं।

वहीं जांच एजेंसियों के अनुसार, शब्बीर लोन का फोकस उन इलाकों पर था जहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। वह ऐसे स्थानों की रेकी करता था, जहां अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। हाल के दिनों में भी उसने कई भीड़भाड़ वाले इलाकों का दौरा कर संभावित हमलों के लिए सर्वे किया था।

अधिकारियों का कहना है कि लोन का नेटवर्क काफी संगठित था और वह तकनीक का इस्तेमाल कर अपने सहयोगियों के संपर्क में रहता था। एन्क्रिप्टेड माध्यमों के जरिए बातचीत कर वह सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने की कोशिश करता था। पुलिस के मुताबिक, शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। वह एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए अपने सहयोगियों के संपर्क में रहता था और उन्हें निर्देश देता था।

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था, जो इसे फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करा रही थी।

पुराना आतंकी, पहले भी हो चुका है गिरफ्तार

शब्बीर अहमद लोन कोई नया नाम नहीं है। वर्ष 2007 में भी उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद, जिसमें एके-47 राइफल और ग्रेनेड शामिल थे, के साथ गिरफ्तार किया था। उस समय उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और वह 2018 तक तिहाड़ जेल में बंद रहा। जेल से बाहर आने के बाद लोन जमानत पर छूट गया और देश छोड़कर बांग्लादेश चला गया। वहीं से उसने दोबारा अपना आतंकी नेटवर्क सक्रिय कर लिया और भारत में स्लीपर सेल तैयार करने लगा।

आतंकी सरगनाओं से सीधे संपर्क

जांच में यह भी सामने आया है कि शब्बीर अहमद लोन के सीधे संबंध लश्कर के सरगना हाफिज सईद और उसके सहयोगी जकी-उर-रहमान लखवी से रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोन ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद स्थित आतंकी कैंप में प्रशिक्षण भी लिया था, जिसमें बेसिक (दौरा-ए-आम) और एडवांस (दौरा-ए-खास) ट्रेनिंग शामिल थी।

नीतीश कुमार का विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने यह कदम राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद उठाया। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे विकासशील मुख्यमंत्री हैं। अब केंद्र जा रहे है। उनके नेतृत्व में बिहार ने विकास को देखा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया जा रहा है। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर तनाव, ट्रंप ने ईरान को दी ऊर्जा ढांचे पर हमले की चेतावनी

वॉशिंगटन। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि स्ट्रेट ऑफ होरमुजा को जल्द 'व्यवसाय के लिए खुला' नहीं किया गया, तो अमेरिका ईरान के नागरिक ऊर्जा ढांचे को निशाना बना सकता है।

सोशल मीडिया पर दिए गए बयान में ट्रंप ने संकेत दिया कि किसी समझौते में देरी होने या जलडमरूमध्य के बंद रहने की स्थिति में अमेरिका ईरान के पावर प्लांट, तेल कुओं और खार्ग द्वीप जैसे अहम ऊर्जा ठिकानों पर कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन ठिकानों को अब तक जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां से दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है।

इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी चिंता गहराती जा रही है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के साथ 'गंभीर बातचीत' कर रहा है और हालिया वार्ताओं में सकारात्मक प्रगति हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ संवाद अप्रत्यक्ष रूप से मध्यस्थों के जरिए चल रहे हैं।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का बिहार विस की सदस्यता से इस्तीफा

पटना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वह विधानसभा में पटना के बांकीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया, 'बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन एवं कार्यकर्ता साथी, जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत की।

दिल्ली में जनगणना का पहला चरण 16 अप्रैल को शुरू होगा

नई दिल्ली। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने सोमवार को बताया कि जनगणना-2027 का पहला चरण 16 अप्रैल को मकान सूचीकरण अभियान के साथ शुरू होगा और इस दौरान सभी संरचनाओं, घरों और परिवारों से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। नारायण ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह प्रक्रिया 30-30 दिनों के दो चरणों में चलेगी। उन्होंने बताया कि नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में यह प्रक्रिया 16 अप्रैल से 15 मई तक चलेगी, जबकि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में इस प्रक्रिया के लिए 16 मई से 15 जून तक की तारीख तय की गई है। एनडीएमसी और दिल्ली छावनी क्षेत्रों के लिए स्व-गणना की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होगी।

भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास 'मरू संग्राम' में दिखाई स्वदेशी हथियार, ड्रोन और टैंक की ताकत

जोधपुर। भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सेना की कोणार्क कॉर्प्स ने राजस्थान के रेगिस्तानी सेक्टर के आगे के इलाकों में रविवार तक युद्ध अभ्यास पूरा किया। यह अभ्यास सुबह से रात तक चला, जिसमें जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी ने मौके पर पहुंचकर टैंक, तोप, हेलीकॉप्टर और ड्रोन सिस्टम का निरीक्षण किया।

अभ्यास में स्वदेशी हथियारों के साथ सेना की तैयारी और अलग-अलग हालात में काम करने की क्षमता को परखा गया। कोर ने आधुनिक तकनीक और युद्धक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपनी बैटल रेडी स्थिति दिखाई। सेना के अनुसार प्रदर्शन के दौरान सेना ने ड्रोन और काउंटर-ड्रोन सिस्टम पर विशेष जोर दिया। निगरानी से लेकर सटीक हमला करने तक, ड्रोन्स की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। साथ ही, दुश्मन के ड्रोन्स को बेअसर करने वाली तकनीक का भी सफल परीक्षण किया गया। रेतीले टीलों के बीच टैंकों और बीएमपी गाड़ियों ने अपनी गति और निशाने की क्षमता दिखाई। मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री यूनिट्स ने कठिन भूभाग में मूवमेंट और ऑपरेशन को परखा, जिससे अलग-अलग युद्ध परिस्थितियों में काम करने की तैयारी जांची गई। तोपखाने में बोफोर्स और अन्य आर्टिलरी गन से लक्ष्य पर सटीक मार की क्षमता का परीक्षण किया गया।

अटैक हेलीकॉप्टरों ने हवा से जमीन पर हमले का अभ्यास करते हुए तय लक्ष्यों को निशाना बनाया। अभ्यास में ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम पर खास ध्यान दिया गया। ड्रोन से निगरानी और लक्ष्य की पहचान की गई, जबकि काउंटर सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने की तकनीक का परीक्षण किया।

पुलिस ने किया डेटिंग ऐप से धोखाधड़ी का खुलासा, तीन शातिर गिरफ्तार

नोएडा। थाना सेक्टर-113 पुलिस ने ग्राइंडर डेटिंग ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी व लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त ऐप के जरिए लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे। इसके बाद चेटिंग करके उनको अपने जाल में फंसाते हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 30 हजार रुपए नकद, 4 मोबाइल फोन सहित अन्य सामान बरामद किया है। एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि पुलिस ने ग्राइंडर डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसा व डरा-धमका कर उनसे रुपये ऐंठने वाले एक गैंग के सरगना समेत तीन शातिरों को दबोचा है। आरोपी ऐप पर लोगों से संपर्क कर उन्हें मिलने के लिए अपने पास बुलाते थे। इसके बाद उनसे पैसे और सामान लूट लेते थे। उन्होंने बताया कि इस अपराध के संबंध में कई लोगों ने पुलिस से शिकायतें की थी।

मामले की जांच पड़ताल कर रही थाना सेक्टर-113 पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से धोखाधड़ी व लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्त शिवम झा पुत्र पवन झा, सागर ठाकुर पुत्र मदन ठाकुर, तथा कमल पुत्र प्रताप राम को सेक्टर-76 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि अभियुक्त संगठित रूप से गैंग बनाकर ऑनलाइन डेटिंग ऐप (ग्राइंडर गे डेटिंग ऐप) के माध्यम से पहले व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर उनसे मित्रता करते हैं। इसके उपरांत वे पीड़ित को किसी निर्धारित स्थान पर मिलने के लिए बुलाते हैं। मुलाकात के दौरान अभियुक्त कार का उपयोग करते हुए पीड़ित को अपने वाहन में बैठाकर उसे डरा-धमकाकर उसके साथ धोखाधड़ी करते हैं तथा उसके माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराकर पैसे निकलवा लेते हैं एवं लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

महिला की मौत के बाद ड्राइवर के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी

यमुना सिटी। जेवर थाना क्षेत्र में प्राइवेट बस से गिरकर हुई महिला की मौत के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। महिला की मौत के बाद उसके बेटे की ओर से थाने में लिखित शिकायत दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने बस ड्राइवर को नामजद किया है दिल्ली निवासी सौरभ शर्मा ने लिखित शिकायत देकर बताया कि 29 मार्च को उनकी मां पुष्पा शर्मा बस में सवार होकर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए दिल्ली से मथुरा जा रही थी। रात को बस लगभग 2 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर शिवा ढ़ाबा के पास रुकी थी। उन्होंने बताया कि उनकी मां शौच जाने के लिए बस से उतर रही थीं, तभी ड्राइवर ने लापरवाही बरतते हुए बस स्टार्ट कर दी। जिससे उनकी मां सिर के बल गिर गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जेवर थाना प्रभारी संजय कुमार ने कहा कि महिला के बेटे की लिखित शिकायत के आधार पर बस ड्राइवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

एक्सप्रेस ट्रेन में चेन पुलिंग का आरोपी गिरफ्तार

दादरी। दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग के रेलवे स्टेशन दादरी के समीप यार्ड में एक्सप्रेस ट्रेन में चेन पुलिंग की गई। चेन पुलिंग करने पर आरपीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर गोमती एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही थी। जब ट्रेन दादरी के समीप यार्ड में पहुंची तो चेन पुलिंग कर दी गई। ट्रेन रुकने पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने चेन पुलिंग करने वाले फिरोजाबाद के बन्ना गांव निवासी प्रखर भारद्वाज को पकड़ लिया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रेलवे अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

यूपीपीसीएस 2024 में दादरी की सगी बहनों ने लहराया परचम

ग्रेटर नोएडा। कहावत है कि प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करते-करते ही सफलता हासिल होती है। यह बात ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र के डेरी मच्छा गांव की दो सगी बहनों पर सटीक बैठती है। चौथे और पांचवें अटेम्प्ट में दोनों बहनों को सफलता हासिल हुई है।

रविवार देर रात को यूपीपीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम जारी हुआ। इसमें गौतम बुद्धनगर की दो बहनों का असिस्टेंट कमिश्नर (कामर्शियल टैक्स) पद पर चयन हुआ है। नेहा नागर को 156 और निधि नागर को 166वीं रैंक मिली है। नेहा नागर ने बताया कि उनका यह चौथा अटेम्प्ट था और दूसरी बार वह इंटरव्यू में शामिल हुई थी। चौथे अटेम्प्ट तक पहुंचाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। वह लगातार हर बार बेहतर करने की सोच रही थी।

इस बार उनका सिलेक्शन हो गया है। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी बहन का पांचवा प्रयास था और वह तीसरी बार इंटरव्यू में बैठी थी। माता-पिता और ईश्वर के आशीर्वाद से दोनों बहनों का एक साथ सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों से भी हार नहीं मानने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संघर्ष भले लंबा हो सकता है, लेकिन जीत हमेशा तय होती है इसलिए हम दोनों बहनों को भी समय अधिक लगा, लेकिन दोनों का सिलेक्शन एक साथ हो गया है। उन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी करके उन्हें सफलता मिली है। दादरी के ही एक निजी स्कूल से उन्होंने हाई स्कूल व इंटर की पढ़ाई की। उन्होंने बताया जब सिलेक्शन नहीं होता था तो सबसे अधिक पिता का सहयोग मिलता था। पिता उन्हें प्रेरणा देते थे कि इस बार नहीं तो अगली बार सफलता जरूर मिलेगी इसलिए मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो।

करिश्मा ने टॉप-20 में जगह बनाकर शहर का नाम रोशन किया

नोएडा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। नोएडा से टॉप 20 में 17 वीं रैंक हासिल कर करिश्मा चौहान ने शहर का नाम रोशन किया है। करिश्मा चौहान ने प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में टाप 20 में जगह बनाई है। करिश्मा के पिता वीरेंद्र चौ और माता सीमा चौहान ने बताया कि बेटी सफलता से बहुत खुशी हुई है। उसकी मेहनत रंग लाई। इस वर्ष 947 पदों के लिए 2719 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए थे। बता दें कि इस बार 10 में 6 लड़कियां शामिल हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवे, छठवें और सातवें स्थान पर लड़कियों ने बाजी मारी है। यह परिणाम प्रारंभिक परीक्षा के एक साल तीन महीने सात दिन बाद घोषित किया है।

मजदूर संगठन 1 अप्रैल को सीटू के आह्वान पर मनायेंगे 'काला दिवस'

नोएडा । केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर 1 अप्रैल को मजदूर संगठनों द्वारा पूरे देश में 'काला दिवस' मनाया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के मकसद से सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू), गौतमबुद्ध नगर इकाई के पदाधिकारियों ने सोमवार को बैठक की। जिसमें जिले के सभी कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण स्थलों, संस्थानों और कार्यस्थलों के मजदूरों, कर्मचारियों एवं यूनियन कार्यकर्ताओं से इस विरोध में शामिल होने की अपील की।

सीटू जिला कमेटी के पदाधिकारियों मुकेश कुमार राघव, रामस्वारथ, सुनील पंडित तथा गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 को श्रमिक-विरोधी चार श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए केंद्रीय नियमों की अधिसूचना घोषित किया है। इन संहिताओं को 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के नाम पर लाया गया है, लेकिन वास्तव में यह यूनियन बनाने और हड़ताल के अधिकार को कुचलती हैं। 8 घंटे के कार्यदिवस को खत्म कर कार्य समय को मालिक की मर्जी पर छोड़ती हैं। ठेका प्रथा और फिक्स्ड टर्म रोजगार को स्थायी बनाती हैं। न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, बोनस, ग्रेच्युटी जैसे अधिकारों को कमजोर करती हैं।

मालिकों के उल्लंघनों को अपराध मुक्त करती हैं, जबकि यूनियन गतिविधियों को दंडनीय बनाती हैं। सीटू ने कहा कि लगभग 150 वर्षों के संघर्ष से हासिल अधिकारों को एक झटके में छीनने का यह प्रयास है, जो मजदूर वर्ग को फिर से औपनिवेशिक गुलामी की ओर धकेलने की साजिश है। जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि 12 फरवरी 2026 की ऐतिहासिक आम हड़ताल में गौतम बुद्ध नगर के श्रमिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था, और उसी जज्बे के साथ 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाएगा।

एक्सप्रेसवे मेट्रो स्टेशनों पर शाम ढलते ही ऑटो का टोटा

नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे किनारे स्थित मेट्रो स्टेशनों पर शाम होते ही ऑटो और ई-रिक्शा का संकट गहराने लगता है। शाम के समय मेट्रो से उतरकर घर पहुंचने में लोगों को खासा परेशानी होती है। काफी इंतजार करने के बाद भी कोई साधन नहीं मिलता है।

नोएडा को एक मॉडल के रूप में तैयार तो कर दिया गया लेकिन सुविधाएं अब भी अधूरी हैं। करोड़ों की कीमत के फ्लैट होने के बाद भी परिवहन व्यवस्था लचर है। नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे के किनारे एक्वा लाइन मेट्रो का संचालन होता है। एक्सप्रेसवे के दूसरे छोर पर अब आबादी बढ़ गई है। मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद घर पहुंचने तक साधन की व्यवस्था नहीं है। सेक्टर 142, 144, 147 और 148

▶▶ सेक्टर 142 और 148 मेट्रो स्टेशन पर उतरते हैं अधिकांश लोग, ऑटो न मिलने पर जाना पड़ता है पैदल

मेट्रो स्टेशन के बाहर शाम के समय ऑटो-ई रिक्शा का अकाल रहता है। परेशानी तब और बढ़ जाती है जब समय बारिश का हो। प्रतीक कैनेरी सोसाइटी के रहने वाले आशीष धामा ने बताया कि कई बार मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद साधन नहीं मिलता है। एग्जॉटिका फ्रेस्को सोसाइटी के निवासी विनीत श्रीवास्तव ने बताया कि सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन से कोई ऑटो नहीं मिलता है। रात के समय ऑनलाइन कैब व बाइक भी आसानी से बुक नहीं होती। जिसके चलते लोगों को मेट्रो स्टेशन से घर तक का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक इस स्थिति में और भी असुरक्षित महसूस करते हैं। स्थानीय निवासियों ने ऑटो और ई-रिक्शा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है।

सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन से लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी, लोटस जिंग, एग्जॉटिका फ्रेस्को, होम्स रिज रेजिडेंसी, निंबस द गोल्डन पाम, द ग्रैंड अरिस्टा सोसाइटी और सेक्टर-167 के निवासी उतरते हैं। सेक्टर-147 मेट्रो स्टेशन से बदौली खादर और सेक्टर-155 के लोग उतरते हैं। सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन पर महागुण मीडोज, एस पार्कवे, अंतरिक्ष गोल्फ सिटी सेक्टर-150, समृद्धि लग्जरिया एवेन्यू, और प्रतीक कैनेरी के निवासी सफर करते हैं।

एक बार फिर लिफ्ट बनी 'जाल', 20 मिनट तक फंसे रहने से महिला की हालत बिगड़ी

नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटियों में लोगों के लिफ्ट में फंसने की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। ताजा मामला सोमवार को एक बार फिर ग्रेनो वेस्ट हिमालय प्राइड सोसाइटी का सामने आया है।

इस घटना की एक वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर वायरल हो रही है। इस सोसायटी में नवमी पर कन्या पूजन के बाद घर जा रही कुछ छोटी बच्चियां व महिलाएं लिफ्ट में फंस गई थी। उसके बाद भी बिल्डर प्रबंधन द्वारा लिफ्ट के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्रेटर नोएडा के हाईराइज सोसाइटियों में लिफ्ट से जुड़े मामले थमने का नाम ही नही ले रहे हैं। आज फिर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाईराइज सोसाइटी हिमालय प्राइड का मामला सामने आया है। यहां लिफ्ट अटकने के दौरान एक युवती लिफ्ट के अंदर करीब 15 से 20 मिनट तक फंसी रही। जिस वजह से युवती की हालत बहुत खराब हो गई। सोसायटी के एओए सचिव मयंक मिश्रा ने बताया कि यहां रोजाना लिफ्ट खराब हो रही है।

हाल ही में नवमी पर कन्या पूजन के बाद घर जा रही कुछ छोटी बच्चियां व महिलाएं लिफ्ट में फंस गई थी। उन्होंने कहा कि बिल्डर प्रबंधन से कई बार लिफ्ट के रखरखाव की शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में आज फिर निवासियों ने नाराजगी जताते हुए मामले की शिकायत रखरखाव प्रबंधन से की है।

निंबस ग्रुप ने जरूरतमंदों के लिए दिए 83 लाख रुपये दिए

ग्रेटर नोएडा। निंबस ग्रुप ने सीएसआर के तहत जरूरतमंदों के लिए 83 लाख रुपये का योगदान दिया। निदेशक यामिनी अग्रवाल ने कहा कि कंपनी के लिए सीएसआर एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लगातार निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। ग्रुप ने कई एनजीओ को सहयोग दिया है। इनमें निवेदिया फाउंडेशन, सेतु फाउंडेशन, संकल्प कैंसर केयर फाउंडेशन, नोएडा डेफ सोसाइटी और ब्राइट द सोल फाउंडेशन जैसी संस्थाएं शामिल हैं।

ये संस्थाएं शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, विशेष बच्चों के पुनर्वास, कैंसर मरीजों के इलाज, बधिर बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की देखभाल जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

ग्रेटर नोएडा के 18 गांवों में अप्रैल से शुरू होगा ओपन जिम कार्य

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए ओपन जिम लगाने का कार्य अप्रैल से शुरू किया जाएगा। प्राधिकरण ने इसके लिए कंपनी का चयन कर कार्य आदेश जारी कर दिया है और विभिन्न स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। प्राधिकरण के अनुसार प्रथम चरण में कासना, सिरसा, डाढ़ा, गिरधरपुर सहित कुल 18 गांवों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों के परिसर और खेल मैदानों में जगह तय की गई है।

प्रत्येक जिम में छह प्रकार के व्यायाम उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके। वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह ने बताया कि इस परियोजना पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। चयनित कंपनी तीन वर्षों तक इन जिम का रखरखाव भी करेगी। गांवों के लोग इन सुविधाओं का निशुल्क लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत सिट-अप स्टेशन, ट्विस्टर, एयर वॉकर, चेस्ट प्रेस, पुलिंग चेयर और लेग प्रेस जैसे उपकरण लगाए जाएंगे। साथ ही सुरक्षित उपयोग के लिए रबर फर्श की व्यवस्था भी की जाएगी। प्राधिकरण ने बताया कि दूसरे चरण में 17 और गांवों में भी ओपन जिम लगाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।

इसके अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विभिन्न सेक्टरों में पार्कों के भीतर ओपन जिम, गार्डन बेंच और झूले लगाने की योजना पर भी काम तेज किया गया है। महाप्रबंधक परियोजना ए. के. सिंह के अनुसार, चरणबद्ध तरीके से सभी गांवों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सके।

एमिटी और क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में अकादमिक सहयोग पर सहमति

नोएडा। एमिटी विश्वविद्यालय और क्वींसलैंड विश्वविद्यालय ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच अकादमिक सहयोग और संयुक्त अनुसंधान को लेकर महत्वपूर्ण पहल की गई है। इस संबंध में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन स्थित विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने एमिटी विश्वविद्यालय का दौरा किया।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रो अना डेलेटिक ने किया, जिसमें विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों के विशेषज्ञ शामिल थे। इस अवसर पर एमिटी विश्वविद्यालय के समूह कुलपति डॉ. गुरिंदर सिंह और एमिटी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. डब्ल्यू सेल्वामूर्ती ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

प्रो अना डेलेटिक ने कहा कि उनका विश्वविद्यालय उद्योग से जुड़े शिक्षण, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और नवाचार के लिए वैश्विक स्तर पर पहचान रखता है। उन्होंने संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र, शोध कार्यक्रम, छात्र विनिमय और उद्योग आधारित परियोजनाओं में सहयोग की संभावनाएं व्यक्त कीं। डॉ. गुरिंदर सिंह ने बताया कि दोनों संस्थान मिलकर रणनीतिक शैक्षणिक साझेदारी स्थापित करेंगे।

इंजीनियरिंग, स्थायित्व, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत सामग्री जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और दोहरी डिग्री कार्यक्रम शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। डॉ. डब्ल्यू सेल्वामूर्ती ने एमिटी में हो रहे शोध, पेटेंट और उनके व्यावसायिक उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी से छात्रों को वैश्विक स्तर पर सीखने और आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक और अधिकारी भी उपस्थित रहे।

दिल्ली: एलजी ने दिए निर्देश, अब कचरे के पहाड़ों से मिलेगी मुक्ति

भलस्वा लैंडफिल साइट पर बायो-रेमीडिएशन तेज करने का उपराज्यपाल का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली को 'कचरे के पहाड़ों' से मुक्त करने के अभियान में तेजी लाने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सोमवार को उत्तर-पश्चिम दिल्ली स्थित भलस्वा लैंडफिल साइट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बायो-रेमीडिएशन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप दिल्ली को इन गंदगी के ढेरों से जल्द निजात दिलाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

विदेशी तकनीक और विशेषज्ञों की ली जाएगी मददः निरीक्षण के दौरान उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पिछले एक साल में हुए कार्यों पर संतोष तो जताया, लेकिन यह भी माना कि अभी लक्ष्य दूर है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कचरा प्रबंधन के लिए केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर न रहें। एलजी ने कहा, "विश्व स्तर पर कचरा निस्तारण के क्षेत्र में आ रही नवीनतम और उभरती हुई तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अध्ययन करें और विशेषज्ञों से परामर्श कर कार्ययोजना में तेजी लाएं।

नए कचरे के प्रवेश पर सख्तीः भलस्वा, गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइट्स पर वर्षों से जमा 'लेगेसी वेस्ट' (पुराना कचरा) तो एक चुनौती है ही, लेकिन प्रतिदिन आने वाला फ्रेश वेस्ट इस समस्या को और जटिल बना रहा है। एलजी ने एमसीडी को कड़े निर्देश दिए कि इन साइटों पर नए कचरे के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने इस अभियान में जन-भागीदारी को अनिवार्य बताते हुए कहा कि दिल्ली भर की रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन को इस मिशन से जोड़ा जाए। एलजी ने जोर दिया कि घरों और बाजारों से ही कूड़े को गीला और सूखा श्रेणियों में अलग-अलग करना सुनिश्चित किया जाए। कूड़े का स्रोत पर ही पृथक्करण होने से बायो-रेमीडिएशन की प्रक्रिया कई गुना तेज हो जाएगी।

गर्मी में आग की घटनाओं को लेकर चेतावनीः गर्मी की आहट के साथ ही लैंडफिल साइट्स पर मीथेन गैस के कारण लगने वाली आग एक बड़ी समस्या बन जाती है। उपराज्यपाल ने इसे लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लैंडफिल साइटों पर आग की घटनाओं को रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम अभी से उठा लिए जाएं। इसके लिए फायर फाइटिंग सिस्टम और निगरानी तंत्र को चौबीसों घंटे अलर्ट पर रखने को कहा गया।

निरीक्षण के दौरान उपराज्यपाल ने वहां काम कर रहे श्रमिकों से भी संवाद किया। उन्होंने श्रमिकों की कार्यप्रणाली और उन्हें पेश आने वाली दिक्कतों को समझा। एलजी ने स्पष्ट आदेश दिया कि संबंधित एजेंसिया साइट पर काम करने वाले हर कर्मचारी के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय और आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करें।

हनुमान जयंती पर उत्तर पश्चिम दिल्ली में हाई अलर्ट

जहांगीर पुरी सहित संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा, ट्रैफिक रहेगा नियंत्रित

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिम जिला दिल्ली पुलिस ने आगामी 2 अप्रैल 2026 को मनाई जाने वाली हनुमान जयंती के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। खासतौर पर जहांगीर पुरी थाना क्षेत्र को संवेदनशील मानते हुए यहां बहु-स्तरीय सुरक्षा योजना तैयार की गई है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।उत्तर-पश्चिम जिले की डीसीपी आकांक्षा यादव ने बताया कि धार्मिक शोभा यात्रा केवल निर्धारित रूट पर ही निकाली जाएगी। इस रूट का चयन सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यात्रा को तय समय सीमा के भीतर ही पूरा करना होगा और इसकी निगरानी पुलिस की कड़ी देखरेख में होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शोभा यात्रा में अधिकतम 500 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, ज्वलनशील या खतरनाक वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही, भड़काऊ नारे, भाषण या सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर सख्त रोक रहेगी। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी निर्धारित नियमों और समय सीमा के अनुसार ही किया जा सकेगा।सुरक्षा व्यवस्था के तहत अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग, पिकेट्स और लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा, ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर स्थिति की निगरानी करेंगे। ट्रैफिक पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।दिल्ली पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि हनुमान जयंती का पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके।

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, बूंदाबांदी व तेज हवाओं से तापमान गिरा

नई दिल्ली। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर का मौसम अचानक बदल गया है। सोमवार को राजधानी में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की धूप रही, जबकि आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी और तेज हवाओं का असर देखने को मिला। फरीदाबाद में दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। वहीं नोएडा में सुबह धूप रहने के बाद दोपहर में तेज हवाएं चलने लगीं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण पूरे क्षेत्र में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

वहीं, राजधानी की वायु गुणवत्ता भी फिलहाल संतोषजनक स्थिति में है। सुबह के समय वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में भी हवा की गुणवत्ता संतोषजनक से मध्यम श्रेणी के बीच बनी हुई है।

ऊंटों पर शराब तस्करी का भंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। राजधानी में शराब तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए ऊंटों का सहारा लिया। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार क्षेत्र में पुलिस ने ऊंटों के जरिए हरियाणा से लाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

दक्षिणी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम को 29 और 30 मार्च की दरम्यानी रात सूचना मिली थी कि फरीदाबाद से जंगल के रास्ते अवैध शराब दिल्ली लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने संगम विहार के जंगल क्षेत्र में जाल बिछाया और कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनोद भड़ाना (48) निवासी आनंदपुर, फरीदाबाद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ऊंटों पर शराब की पेटियां लादकर सुनसान जंगल मार्ग से दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, ताकि चेकिंग से बच सके। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 39 कार्टन अवैध शराब, जिसमें कुल 1,938 क्वार्टर शामिल हैं, बरामद किए। इसके अलावा शराब ढोने में इस्तेमाल किए जा रहे दो ऊंट और अन्य सामान भी जब्त किया गया। बरामद ऊंटों को संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। जांच में सामने आया है कि दिल्ली-फरीदाबाद सीमा पर कड़ी निगरानी के चलते आरोपी ने यह अनोखा तरीका अपनाया था। वह सड़कों की बजाय जंगल के रास्तों का इस्तेमाल कर पुलिस की नजरों से बचकर तस्करी कर रहा था।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पहले भी वर्ष 2025 में नेब सराय थाने में दिल्ली आबकारी अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे तस्करी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।

सोशल मीडिया पर पिस्तौल के साथ वीडियो-फोटो डालना पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह के निर्देश पर सोशल मीडिया पर अवैध रूप से हथियारों का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस तरह की गतिविधियों में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पिस्तौल भी बरामद हुई है। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए थे, जिनमें वह भय पैदा करने और अनुचित ध्यान आकर्षित करने के इरादे से हथियार लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की पहचान और पता लगाने के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। जिसमें इंस्पेक्टर कमलेश कुमार – प्रभारी विशेष स्टाफ, एसआई राकेश, एएसआई करतार, हेड कांस्टेबल सुधीर, कुलदीप कांस्टेबल रवि और हेमराज शामिल थे। टीम ने सोशल मीडिया निगरानी और खुफिया जानकारी की सहायता से वीरेंद्र खरब (26) निवासी वीपीओ मुंडेला को अत्याधुनिक पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। जाफरपुर कलां थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

दिल्ली पुलिस मुख्यालय में भव्य पिपिंग सेरेमनी

145 कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर मिला मानद पदोन्नयन

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस मुख्यालय स्थित आदर्श ऑडिटोरियम में एक भव्य पिपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त हो रहे 145 पुलिस कर्मियों को मानद पदोन्नति प्रदान की गई। यह कार्यक्रम मानद रैंक प्रमोशन योजना के तहत आयोजित किया गया, जो दिसंबर में शुरू होने के बाद से चौथी बार आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने की। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर कॉन्स्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक के कर्मियों को उनके अगले मानद रैंक के बैज पहनाकर सम्मानित किया।अपने संबोधन में पुलिस आयुक्त ने सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समारोह में दिख रही खुशी और गर्व की भावना दिल्ली पुलिस को और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी इन कर्मियों का रिश्ता दिल्ली पुलिस परिवार से हमेशा बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस सेवा केवल नौकरी नहीं बल्कि एक जुनून है, जिसके तहत कर्मियों ने 35-40 वर्षों तक कठिन परिश्रम और लंबे कार्य घंटों में सेवा दी।

बुजुर्गों की देखभाल के लिए केंद्र सरकार पृथक मंत्रालय बनाये : एम के रैना

देश में वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा पर सेमिनार एवं सम्मान समारोह

नई दिल्ली। हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। दुनिया में सबसे तेज विकास करने वालों में हिंदुस्तान चोटी पर है, पर सरकार को देश के वरिष्ठ नागरिकों की परवाह नहीं है। यह उद्गार हैं अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ, AISCON के अध्यक्ष एम के रैना का। आई टी ओ स्थित मालवीय स्मृति भवन में रविवार को आयोजित सेमिनार एवं सम्मान समारोह में रैना ने कहा कि सरकार की नज़र में वरिष्ठ नागरिकों का महत्व नहीं के बराबर है। दुनियाभर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम है। यदि देश की सभी इकाइयाँ एकजुट होकर आवाज़ उठाएं तो सरकार को हम पर जरूर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा की वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने के लिए केंद्र सरकार को एक अलग मंत्रालय बनाना चाहिए।

उन्होंने खचाखच भरे सभागार में लोगों का आह्वान किया कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत रहे वरिष्ठ नागरिकों को खुश रहने का बहाना ढूँढना होगा। आपको खुश रहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। शार्प साइट आई इंस्टिट्यूट के संस्थापक समीर सूद ने साल में एकबार आँखों की आवश्यक जांच कराने पर जोर दिया। उनका अस्पताल ग्रामीण इलाकों में बुजुर्गों की आँखों के इलाज के लिए चार सौ केन्द्र खोलने जा रही है। पिछले 25 सालों से देशभर के बुजुर्गों की देखभाल में जुटी अनुग्रह नामक गैर लाभकारी संस्था की अध्यक्ष आभा चौधरी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज पर कोई बोझ नहीं हैं। जापान में रोबोट बुजुर्गों की देखभाल करते हैं। हांगकांग में हर रेजिडेंट अपार्टमेंट में केएर टेकर नियुक्त हैं, जबकि भारत में लोग उपेक्षित हैं।

छोटे सिलेंडर से हमला कर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा

नई दिल्ली। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में रविवार देर रात पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने रविवार रात कथित तौर पर घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी के सिर पर छोटे गैस सिलेंडर से कई बार वार करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद बच्ची को गोद में लिए शव के पास बैठा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पति को हिरासत में ले लिया।

आरोपी के एक पड़ोसी ने कहा, सुरेश ने अपनी पत्नी पूनम की हत्या कर दी, जिसकी 18 महीने की एक बच्ची है। दोनों एक महीने से डीडीए आवास में रह रहे थे। पति ने कथित तौर पर चरित्र पर शक के चलते पत्नी की हत्या की है। पति ने सिलेंडर से पत्नी के सिर पर पहले वार किया फिर हाथ तोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्ची हमारे पास है, जिसे परिचितों को सौंप दिया जाएगा। आरोपी को पुलिस अपने साथ ले गई। एक दूसरे पड़ोसी ने बताया, रविवार रात में बचा लो, बचा लो की आवाज आई थी। अपने रूम से नीचे उतरकर आया तो पता चला कि प्रथम तल पर झगड़ा हुआ है। जिस रूम से आवाज आई थी वहां गए तो अंदर से दरवाजा बंद था। इसके बाद मकान मालिक को बुलाया, जिन्होंने दरवाजा खोला। अंदर जाकर देखा तो महिला मृत पड़ी थी और बगल में सिलेंडर पड़ा था। शव के बगल में पति बच्ची को लिए खड़ा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

गौरतलब है कि 17 मार्च की देर रात रानीबाग इलाके में शादी समारोह में कुछ युवकों के बीच खाने को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि हाथापाई होने लगी। इसी दौरान पास के ही नाहरपुर गांव का रहने वाला 17 वर्षीय निखिल यादव बीचबचाव करने पहुंचा। जैसे ही निखिल ने बीच-बचाव की कोशिश की तो हमलावर युवकों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। हमला इतना तेज था कि निखिल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, बचाव में आए एक अन्य युवक को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।

मुख्यमंत्री ने गौसेवा के लिए जारी किए 20.26 करोड़ रुपये

गौशालाओं को लीज विस्तार और बायोगैस सहायता

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में गायों की सेवा, संरक्षण और संवर्धन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए राजधानी की गौशालाओं को लीज एक्सटेंशन समझौते के प्रमाणपत्र प्रदान किए। इस अवसर पर गौशालाओं में आधुनिक बायोगैस इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता भी वितरित की गई।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार की पशुपालन इकाई के तहत चल रही चार गौशालाओं सुल्तानपुर डबास, रेवला खानपुर, हरेवली और सुरहेड़ा के प्रतिनिधियों को चारा भुगतान, बकाया रकम और लाइसेंस/लीज नवीनीकरण से जुड़े आदेश दिए। ये गौशालाएं स्थानीय निकायों द्वारा लाए गए निराश्रित गौवंश की देखभाल, भोजन और इलाज की व्यवस्था करती हैं।

दिल्ली सरकार ने इस पहल के तहत कुल लगभग 20.26 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें 7.64 करोड़ रुपये जून 2024 से मार्च 2025 तक के बकाया भुगतान के लिए और 12.62 करोड़ रुपये अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक के चारे के खर्च के लिए दिए गए हैं। साथ ही, चारों गौशालाओं के लंबे समय से लंबित लाइसेंस और लीज समझौते भी नवीनीकृत कर दिए गए हैं ताकि वहां गौवंश को लगातार भोजन, सुरक्षित रहने की जगह और बेहतर इलाज मिल सके। इस पहल का उद्देश्य गोबर से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छता को भी सुदृढ़ करना है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली सरकार निराश्रित गौवंश की समुचित देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है और गौशालाओं के माध्यम से इस दिशा में ठोस कार्य कर रही है। प्रथम चरण में 10 आधुनिक गौशालाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां निराश्रित गौमाता की सेवा, संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य शीघ्र ही 40 गौशालाओं को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस करना है ताकि सेवा, गोबर से ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छता के इस अभियान को व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली की गौशालाओं को केवल पशु आश्रय स्थल नहीं, बल्कि सेवा और करुणा के जीवंत केंद्रों के रूप में देखती है। आवारा पशुओं, विशेषकर बेसहारा गायों का संरक्षण किया जाना चाहिए। इन गौशालाओं द्वारा निभाया जा रहा दायित्व सराहनीय है क्योंकि वे इन मूक प्राणियों को न केवल आश्रय बल्कि चिकित्सा और पोषण भी प्रदान कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं का उचित प्रबंधन केवल सरकारी बजट से नहीं, बल्कि सरकार और समाज के बीच निरंतर सहयोग और मानवीय संवेदनाओं के मेल से ही संभव है। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की गौशालाओं को अत्याधुनिक सुविधाओं और बेहतर पशु चिकित्सा सेवाओं से लैस करना है ताकि वहां रहने वाले गोवंश को समुचित देखभाल मिल सके।

यह पहल केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि दिल्ली सरकार पशु अधिकारों और उनके प्रति मानवीय व्यवहार के प्रति पूरी तरह सजग है। आने वाले समय में गौशाला प्रबंधनों के साथ मिलकर नई तकनीकों और बेहतर चारा प्रबंधन प्रणालियों पर काम किया जाएगा।

संपादकीय

एक गलत आकलन का घातक परिणाम

अमेरिका-इजरायल व ईरान के बीच युद्ध को एक महीना पूरा हो चुका है। अभी तक इसके समाप्त होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों ने ऐसी शर्तें रखी हैं जिन्हें पूरा करना उन दोनों पक्षों के लिए लगभग नामुमकिन ही है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किये और सऊदी अरब द्वारा समझौता कराने के प्रयासों के बावजूद दोनों पक्षों का अड़ियल रवैया वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी आर्थिक बोझ डालने वाला है। समुद्री तेल और गैस व्यापार का एक चौथाई हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है। ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट में खनन और नाकेबंदी ने तेल की कीमतों को 73 डॉलर प्रति बैरल से बढ़ाकर 110 से 120 डॉलर तक पहुंचा दिया है, साथ ही इसकी भारी कमी भी पैदा हो गई है। पूर्वी एशिया पर इसका विशेष रूप से गंभीर असर पड़ा है क्योंकि 80 से 90 फीसदी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी मार्ग से आते हैं। सऊदी अरब ने नाकेबंदी का सामना करने के लिए अपने पूर्व-पश्चिम स्थलीय पाइप लाइन से लाल सागर के यनबू बंदरगाह तक तेल प्रवाह बढ़ाने की कोशिश की। जिससे कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम तो हुआ लेकिन अब वह मार्ग भी खतरे में है। स्वेज नहर व लाल सागर दुनिया के कंटेनर यातायात का एक-तिहाई हिस्सा संभालता है। लेकिन दुनिया यहां पहले ही 2023-24 में हूती व्यवधानों का असर देख चुकी है। जहाजों को अफ्रीका के पश्चिमी तट से नीचे और केप ऑफ गुड होप के चारों ओर लंबा मार्ग लेना पड़ा, जिससे शिपिंग लागत, बीमा प्रीमियम सहित अन्य खर्च बेतहाशा बढ़ गए। इस बात की अब लगभग पुष्टि हो चुकी है कि अमेरिका व इजरायल ने ईरान की प्रतिक्रियाओं और क्षमताओं का गलत आकलन किया है। ईरान के राजनैतिक और सुरक्षा नेतृत्व की हत्या ने भी उसे आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित नहीं किया। इसके विपरीत, ईरान ने अपने विरोधियों को लगातार चकमा देने वाले विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल किया। दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों से एक महीने तक ईरान पर हमले करने के बावजूद, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि उसके मिसाइल भंडार और ड्रोन क्षमता का लगभग एक-तिहाई हिस्सा ही नष्ट हुआ है। बाकी की स्थिति को लेकर वे अनिश्चित हैं। एक ऐसा देश जिसने ठीक इसी परिस्थिति के लिए योजना बनाई है और जिसे लंबे युद्ध और कठिनाइयों का अनुभव है, उसके लिए लंबा, असमान और थकाऊ युद्ध कोई नुकसान नहीं माना जाता। लेकिन अमेरिका और इजरायल के लिए सम्मान जनक निकास का रास्ता न मिलने से पश्चिम एशिया में स्थाई शांति की संभावना लगातार दूर होती जा रही है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता

भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध ऐतिहासिक रूप से रणनीतिक और बहुआयामी रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार में भारत को अधिशेष प्राप्त हुआ है, जो यह संकेत देता है कि भारतीय कृषि उत्पादों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता मौजूद है। प्रस्तावित समझौते के तहत अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों—जैसे मसाले, चाय, कॉफी, काजू, आम, पपीता और प्रसंस्कृत खाद्य—पर शुल्क में कमी या समाप्ति भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित कर सकती है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि होगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिल सकता है। किन्तु इस समझौते का दूसरा पक्ष कहीं अधिक जटिल और संवेदनशील है। अमेरिका अपने किसानों को व्यापक सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे उसके कृषि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अत्यंत प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। यदि ऐसे उत्पाद—जैसे DDGS, सोयाबीन तेल और ज्वार—भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर प्रवेश करते हैं, तो घरेलू किसानों को मूल्य प्रतिस्पर्धा में गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (2026) ऐसे समय में उभरकर सामने आया है, जब भारत एक ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी को विस्तार देने की दिशा में अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर अपनी कृषि-आधारित सामाजिक-आर्थिक संरचना की रक्षा करने की अनिवार्य चुनौती का सामना कर रहा है। फरवरी 2026 में घोषित अंतरिम रूपरेखा ने जहां भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में नए अवसरों के द्वार खोले हैं, वहीं सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पादों के संभावित आयात ने देश के करोड़ों किसानों के बीच चिंता और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। इस संदर्भ में यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है कि क्या यह समझौता भारत को एक सशक्त वैश्विक कृषि निर्यातक के रूप में स्थापित करेगा या यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन सकता है।

भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध ऐतिहासिक रूप से रणनीतिक और बहुआयामी रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार में भारत को अधिशेष प्राप्त हुआ है, जो यह संकेत देता है कि भारतीय कृषि उत्पादों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता मौजूद है। प्रस्तावित समझौते के तहत अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों—जैसे मसाले, चाय, कॉफी, काजू, आम, पपीता और प्रसंस्कृत खाद्य—पर शुल्क में कमी या समाप्ति भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित कर सकती है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि होगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिल सकता है। किन्तु इस समझौते का दूसरा पक्ष कहीं अधिक जटिल और संवेदनशील है। अमेरिका अपने किसानों को व्यापक सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे उसके

कृषि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अत्यंत प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। यदि ऐसे उत्पाद—जैसे DDGS, सोयाबीन तेल और ज्वार—भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर प्रवेश करते हैं, तो घरेलू किसानों को मूल्य प्रतिस्पर्धा में गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जो पहले से ही आय संकट से जूझ रहे किसानों के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न करेगी।

भारत की कृषि संरचना मुख्यतः छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित है, जो कुल किसानों का लगभग 86% हिस्सा हैं। ये किसान सीमित संसाधनों, अस्थिर बाजार और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच अपनी आजीविका बनाए रखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी नीतियां इन किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं, किंतु इसकी पहुंच सीमित है और यह सभी फसलों तथा क्षेत्रों को समान रूप से लाभ नहीं पहुंचा पाती। ऐसे में यदि सस्ते आयात घरेलू बाजार में बढ़ते हैं, तो MSP की प्रभावशीलता कमजोर हो सकती है और किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण चिंता जैव-सुरक्षा और जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फसलों से जुड़ी हुई है। अमेरिका GM फसलों का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है, जबकि भारत में इस विषय पर अभी भी सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है। व्यापार समझौते के तहत गैर-शुल्कीय बाधाओं को कम करने का दबाव भारत पर पड़ सकता है, जिससे GM उत्पादों के आयात की संभावना बढ़ सकती है। यह स्थिति देश की जैव-विविधता, पारंपरिक कृषि पद्धतियों और खाद्य सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक जोखिम उत्पन्न कर सकती है। इसके अतिरिक्त, डेयरी, पोल्ट्री और तिलहन जैसे संवेदनशील क्षेत्र भी इस समझौते से प्रभावित हो सकते हैं। भारत का डेयरी क्षेत्र न केवल विश्व में अग्रणी है, बल्कि यह करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का आधार भी है। यदि अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में प्रवेश करते हैं, तो स्थानीय उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार तिलहन क्षेत्र, जिसमें भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयासरत है, सस्ते आयातों के कारण प्रभावित हो सकता है, जिससे घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने में बाधा उत्पन्न होगी।

इन आर्थिक चुनौतियों के साथ-साथ इस समझौते के सामाजिक और रणनीतिक आयाम भी महत्वपूर्ण हैं। कृषि क्षेत्र में संभावित आय हानि और प्रतिस्पर्धा से ग्रामीण रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे सामाजिक असमानता और क्षेत्रीय विषमताएँ बढ़ सकती हैं। वहीं रणनीतिक दृष्टि से यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक है, जो QUAD और Indo-Pacific में शक्ति संतुलन के व्यापक परिप्रेक्ष्य से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में भारत के लिए इस समझौते को पूरी तरह अस्वीकार करना व्यवहारिक नहीं है, बल्कि संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

इस संदर्भ में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह वैश्विक आर्थिक अवसरों का लाभ उठाते हुए अपने कृषि हितों की रक्षा कैसे करे। इसके लिए बहु-स्तरीय रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, व्यापारिक सुरक्षा उपायों—जैसे मात्रा सीमाएँ (TRQ), न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) और विशेष संरक्षण उपाय (SSM)—का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि अचानक बढ़ते आयातों से घरेलू बाजार को सुरक्षित रखा जा सके। दूसरे, घरेलू कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं। इसमें कृषि उत्पादक संगठनों (FPOs) को बढ़ावा देना, आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना और प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करना शामिल है। इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और किसान बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। तीसरे, निर्यातोन्मुख कृषि नीति को मजबूत किया जाना चाहिए। भारत के पास मसाले, जैविक उत्पाद, बागवानी फसलें और पारंपरिक खाद्य उत्पादों में वैश्विक बाजार पर कब्जा करने की अपार संभावनाएँ हैं। यदि इन क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों, ब्रांडिंग और लॉजिस्टिक्स पर ध्यान दिया जाए, तो भारत न केवल व्यापार संतुलन बनाए रख सकता है, बल्कि उसे और सुदृढ़ भी कर सकता है। चौथे, जैव-सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को लेकर स्पष्ट और सख्त नीति अपनाना आवश्यक है, ताकि देश की खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन से समझौता न हो। इसके साथ ही, तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संतुलन स्थापित करना होगा।

अंततः, यह समझौता केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की विकास यात्रा की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें निहित अवसरों और जोखिमों के बीच संतुलन स्थापित करना ही इसकी सफलता की कुंजी होगा। भारत को "नेशन फर्स्ट" दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसी रणनीति विकसित करनी होगी, जो किसानों की सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा—इन तीनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। यदि भारत स्मार्ट और संवेदनशील नीति-निर्माण के माध्यम से इस संतुलन को साधने में सफल होता है, तो यह समझौता न केवल आर्थिक प्रगति का माध्यम बनेगा, बल्कि देश के करोड़ों किसानों के लिए स्थायी समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

सरकारी स्कूलों पर गहराता संकट, निजीकरण का बोलबाला

- डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। पिछले एक दशक में लगभग 94 हजार सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, जबकि इसी अवधि में 51 हजार से अधिक निजी स्कूल खुल गए हैं। यह स्थिति न केवल सरकारी शिक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करती है बल्कि बढ़ते निजीकरण के कारण उत्पन्न सामाजिक असमानता को भी सामने लाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह अधिकार धीरे-धीरे कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। साल 2014-15 से 2023-24 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या 11,07,101 से घटकर 10,17,660 रह गई, यानी लगभग 89,441 स्कूल कम हो गए, जबकि निजी स्कूलों की संख्या 2,88,164 से बढ़कर 3,31,108 हो गई। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए चिंताजनक है, जहां गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच लगातार कठिन होती जा रही है।

सरकारी स्कूलों के संकट का एक प्रमुख कारण स्कूल मर्जर नीति है, जिसके तहत कम नामांकन वाले छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों में मिला दिया जाता है। इससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के लिए स्कूल

तक पहुंच कठिन हो गई। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हजारों स्कूल बंद हुए हैं, जो कुल बंदी का बड़ा हिस्सा हैं।

इसके अलावा, शिक्षकों की कमी, कमजोर आधारभूत संरचना और मिड-डे मील जैसी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन न होना भी नामांकन में गिरावट के प्रमुख कारण हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ प्रावधान, जैसे एकल शिक्षक स्कूलों को हतोत्साहित करना भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी स्कूलों में नामांकन में भारी कमी आई है। जबकि निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है। गरीब परिवारों के बच्चे अब मजबूरन निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं लेकिन ऊंची फीस उनके लिए बड़ी बाधा बन जाती है। निजी स्कूलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हालांकि यह वृद्धि कई चिंताएं भी पैदा करती है। निजी स्कूलों में फीस में भारी वृद्धि देखी जा रही है, जिससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। शिक्षा का यह बढ़ता निजीकरण उसे एक सामाजिक सेवा से अधिक एक व्यापार में बदलता जा रहा है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिससे सामाजिक असमानता और गहरी हो रही है। एक ओर संपन्न वर्ग बेहतर संसाधनों और सुविधाओं वाले निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करता है, वहीं दूसरी ओर गरीब वर्ग सीमित संसाधनों वाले सरकारी स्कूलों तक ही सीमित रह जाता है।

इस असंतुलन का सीधा प्रभाव ड्रॉपआउट दर पर भी पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लाखों बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, जिनमें बड़ी संख्या किशोरियों की है। इसके पीछे गरीबी, बाल श्रम, परिवार का प्रवास, स्कूलों की दूरी और सुरक्षा की कमी जैसे कई कारण जिम्मेदार हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाता है। जब परिवार निजी स्कूलों की फीस वहन नहीं कर पाते और आसपास सरकारी स्कूल उपलब्ध नहीं होते तो बच्चों का शिक्षा से बाहर होना लगभग तय हो जाता है। यह स्थिति आने वाले समय में बेरोजगारी और सामाजिक असमानता को और अधिक बढ़ा सकती है।

शिक्षा का निजीकरण केवल शैक्षिक समस्या नहीं है बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी गहराता है। जब सभी वर्गों को समान शिक्षा के अवसर नहीं मिलते, तो समाज में अवसरों का असंतुलन बढ़ता जाता है। भारत में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल लगभग 3 प्रतिशत ही खर्च किया जाता है, जबकि इसे 6 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य अभी भी अधूरा है। इसका प्रभाव महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार के अवसरों और देश के समग्र आर्थिक विकास पर पड़ता है। यदि यह स्थिति बनी रही, तो यह लोकतंत्र के लिए भी खतरा बन सकती है क्योंकि एक शिक्षित समाज ही जागरूक और जिम्मेदार नागरिक तैयार करता है। इस संकट से निपटने के लिए सरकार को ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे। स्कूल मर्जर नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्कूलों को संरक्षित किया जाना चाहिए। रिक्त शिक्षक पदों को शीघ्र भरा जाए और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, स्वच्छ पेयजल और डिजिटल संसाधन सुनिश्चित किए जाएं। मिड-डे मील योजना की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण तथा निगरानी बढ़ाई जाए। शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए और शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर इसे सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। निजीकरण का बढ़ता प्रभाव सरकारी स्कूलों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। सरकारी स्कूलों की घटती संख्या और निजी स्कूलों की बढ़ती संख्या यह संकेत देती है कि शिक्षा धीरे-धीरे एक मौलिक अधिकार से हटकर एक व्यापार का रूप लेती जा रही है। इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब और वंचित वर्गों पर पड़ रहा है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो यह असमानता समाज को गहराई तक प्रभावित करेगी।

जीवन सार्थक बनाने के लिए केवल यह एक काम जरूरी

वर्षा के जल से धुलकर स्वच्छ हो चुकी मधुकामिनी की एक सुंदर घनी झाड़ी पर छोटे-छोटे सफेद आकर्षक फूल खिले हुए थे। मैंने उस झाड़ी से एक फूल तोड़ लिया। उसमें से मंद-मंद मनमोहक महक निःसृत हो रही थी। मैंने फूल पर लगी वर्षा जल की नन्ही बूंदों को झाड़ने के लिए फूल के वृंत को अंगूठे व तर्जनी की सहायता से घुमाया तो उसकी पंखुड़ियां ही झरकर नीचे गिर गईं और उंगलियों के बीच रह गया सिर्फ वृंत। मैंने नीचे गिरी सभी पंखुड़ियों को उठाकर हथेली पर रख लिया। उनमें व्याप्त सुगंध अब भी मेरी नासिकाओं तक पहुंच रही थी। पूरी तरह से बिखर जाने के बाद भी फूल के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया था। न रंग में और न गंध में ही। उसकी उपयोगिता में कोई अंतर नहीं आया। फूल में व्याप्त गंध व रंग ही उसे उपयोगी बनाते हैं। फूलों में व्याप्त यह गुण हम सबके लिए अनुकरणीय है। हम विभिन्न अवसरों पर दूसरों को फूल या पुष्पगुच्छ भेंट करते हैं। मन को मन से जोड़ने का कार्य करते हैं फूल। जन्म से लेकर मृत्यु तक सबका शृंगार करते हैं ये। कोई भी मांगलिक अवसर, कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ नहीं हो सकता यदि तरह-तरह की फूल-पत्तियां न हों। आकर्षण, आनंद, प्रेम व सम्मान का ही दूसरा नाम है फूल। फूल बनने से पहले की अवस्था भी कम आकर्षक नहीं होती। एक कली से फूल बनने की यात्रा में जो सहजता व उत्प्रेरणा है वह भी अद्वितीय है। बिना किसी आवाज के रंग व गंध की मंजूषा खुल पड़ती है। जब तक तनिक भी बू-बास, रंग व आकार शेष रहता है लोकरंजन में लगा रहता है सुमन और जब मुरझाने लगता है तो फल में परिवर्तित होकर सृष्टि के विस्तार व वसुधा की क्षुधा तृप्ति में भी अपना योगदान देना नहीं भूलता। मनुष्य को चाहिए कि वह भी ऐसा व्यवहार करे जिससे लोग उसके कार्यों और व्यवहार के लिए उसे भी फूलों की तरह ही पसंद करें। मनुष्य को चाहिए कि वह भी जीवन के हर मोड़ पर फूलों की तरह ही अपनी सार्थकता का प्रमाण दे। एक युवक के रूप में अपने माता-पिता व अन्य की प्रसन्नता व गौरव का कारण बने। गृहस्थाश्रम में परिवार को खुशियों से भर दे, जिस तरह फूल आसपास के वातावरण में सुगंध भर देता है।

आज का इतिहास

1504 - सिखों के गुरु अंगद देव जी का जन्म। वह गुरु नानक देव जी के बाद सिखों के दूसरे गुरू थे।
1727 - दुनिया के महान भौतिकशास्त्रियों में शुमार आइजक न्यूटन का 84 वर्ष की आयु में लंदन में निधन।
1774 - भारत में डाक सेवा शुरू, पहला डाकघर खुला।
1870 - अमेरिका में पहली बार किसी अश्वेत नागरिक ने वोट दिया। अश्वेतों को समान अधिकार दिलाने की दिशा में यह एक बड़ी कामयाबी थी।
1889 - पेरिस का मशहूर एफेल टावर आधिकारिक तौर पर खुला।
1959 - 14वें दलाई लामा, तेनज़िन ग्यातसो, भारत की सीमा पार करी और राजनीतिक में शरण ली।
1980 - अमेरिका के महान फर्राटा धावक जेसी ओवंस का निधन। ओवंस ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में अपने देश के लिए चार स्वर्ण पदक जीते थे।
1981 - एक घरेलू विमान का अपहरण करने वाले इंडोनेशिया के पांच आतंकवादियों में से चार को थाइलैंड के बैंकाक में मार गिराया गया। विमान में सवार सभी 55 लोग सुरक्षित।
1983 - कोलम्बिया में भूकंप से लगभग 5000 लोगों की मौत।
1989 - पैरिस की पहचान माने जाने वाले विशाल एफिल टावर को आधिकारिक तौर पर खोला गया। फ्रांस की क्रांति की शताब्दी के मौके पर बनी 300 मीटर ऊंची लोहे की इस इमारत को गुस्ताव एफिल की प्राद्यौगिक कुशलता का बेमिसाल नमूना माना जाता है।
1990 - संविधान निर्माता डॉ भीमराव आंबेडकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया।
1997 - वासलेव क्लार्क को नया नाटो सैनिक कमांडर नियुक्त किया गया।
1998 - भारत और चीन इंटर गवर्नमेंटल कांफ्रेंस आन कल्चरल पॉलिसीज के लिए गठित यूनेस्को की मसौदा समिति के सदस्य निर्वाचित।
2000 - 22 वर्ष बाद जापान के उत्तरी धोकाइडु द्वीप में दाते के निकट उसू ज्वालामुखी फिर सक्रिय।
2001 - यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति मिलोसेविच की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस का धावा, अपने ही घर में नजरबंद, यूरोपीय मंत्रियों ने क्योटो संधि को जीवित घोषित किया।

संकट के दौर में वैश्विक पर्यटन उद्योग

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के साइड इफेक्ट के रुप में दुनिया का पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक अनुमान के अनुसार 152 करोड़ पर्यटकों से गुलजार रहने वाले वैश्विक पर्यटन उद्योग के मौजूदा हालात के चलते अतिमंदी के दौर से गुजरने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे तो सभी देशों में पर्यटन उद्योग पर विपरीत असर पड़ने जा रहा है पर सबसे अधिक असर मध्य पूर्व के देशों में देखा जा सकता है। जानकारों के अनुसार अकेले मध्य पूर्व को ही 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान भुगतना पड़ सकता है। दुनिया में सबसे अधिक पर्यटक फ्रांस की धरती पर जाते हैं और माना जाता है कि 9 से 10 करोड़ पर्यटक तो फ्रांस का रुख करते हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है, हमारे यहां भी लगभग 2 करोड़ विदेशी पर्यटक देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख करते हैं। पर मौजूदा हालात के चलते विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही पर विपरीत प्रभाव पड़ना ही है।

एक सकारात्मक पक्ष यह देखा जा सकता है कि भारत और दुनिया के देशों में देशी पर्यटकों की संख्या में उछाल के चलते इस उद्योग को संजीवनी अवश्य मिलती लगती है। वर्तमान दौर में दुनिया के चौधरी बने देशों को यह समझ लेना चाहिए कि अब वह जमाना गया जब हफ्ते दो हफ्ते में युद्ध का फैसला हो जाया करता था। आज छोटे-

से छोटा देश भी युद्ध को लंबा खींचने की कूवत रखता है। इसे हम रुस-यूक्रेन युद्ध से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अमेरिका ने भी जब ईरान पर आक्रमण किया तो ट्रंप भी इसी मुगालते में थे कि दो-चार दिन में ईरान के घुटने टिकवा देंगे पर सारे कयास धरे के धरे रह गए और इनके चक्कर में दुनिया अस्थिरता और संकट में और आ गई। आज हालात यह हो गए हैं कि युद्ध तो आप शुरु कर सकते हैं पर युद्ध शुरु होने के बाद कब बंद होगा यह आपके हाथ में नहीं रहेगा।

युद्ध के चलते हालात ऐसे हो गए हैं कि चाह कर भी पर्यटक घूमने का रुख नहीं कर पा रहे हैं। केवल और केवल ट्रंप के दादागिरी के चलते दुनिया के देशों की जीडीपी में करीब 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी निभाने वाला पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। होटल और ट्रैवल उद्योग से जुड़ी एजेंसियों के सामने बड़ा संकट आ गया है तो दुनिया के देशों और संस्कृतियों से जुड़ने और समझ कर एक-दूसरे के नजदीक आने की जो पहल पर्यटन उद्योग के चलते हुई थी उस पर लगभग विराम के हालात होते जा रहे हैं। 10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का पर्यटन उद्योग आज संकट के दौर में आ गया है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी पर्यटन उद्योग की है और वह लगातार दूसरे साल गंभीर संकट के दौर में आ गई है। जैसे-तैसे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हजार डॉलर प्रतिदिन के लग्जरी कमरों की कीमत घटकर 300 डॉलर तक कर देने के बाद भी पर्यटक रुख नहीं कर रहे हैं। हालात विकट होते जा रहे हैं।

दरअसल वैश्विक हालात के चलते एक ओर उड़ानें रद्द होती जा रही है तो युद्ध के चलते लोगों में असुरक्षा की भावना घर कर रही है। ऐसी आशंका होती है कि कब कहां क्या हो जाए और कहीं जाएं वहीं पर बंद होकर न रह जाएं। मध्य-पूर्व के देशों में तो लगभग यही हालात है। कब किस देश और किस स्थान पर मिसाइल अटैक हो जाए, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अमेरिका-इजरायल व ईरान युद्ध की खास नकारात्मक बात यह है कि इन दो देशों पर मिसाइल अटैक नहीं हो रहे बल्कि इनसे थोड़ी भी सहानुभूति रखने वाले देश कब निशाने पर आ जाएं, कहा नहीं जा सकता। मध्य-पूर्व में मिसाइल अटैक और हार्मुज जलडमरुमध्य के हालात इसके उदाहरण हैं।

हालात तो यहां तक खराब होने की आशंका है कि मध्य-पूर्व के देशों में पानी का गंभीर संकट हो सकता है। आज कच्चा तेल, एलपीजी की ही समस्या नहीं अपितु दुनिया को जोड़ने वाले इंटरनेट के बाधित होने की आशंकाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। लगता है एक-दूसरे के अहम् के चलते आम आदमी कहीं हाशिये में चला गया है। युद्ध के सामान्य नियम ताक में रख दिए गए हैं और आम नागरिकों, बच्चों, अस्पतालों, घनी आबादी इलाकों में भी मिसाइल दागने से कोई परहेज नहीं रह गया है। कोरोना के दौरान जिस तरह पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ था आज उसी तरह के हालात बनते दिख रहे हैं। कोरोना के बाद पिछले सालों में पर्यटन उद्योग ने तेजी पकड़ी थी और लगने लगा था कि 2030 तक पर्यटन उद्योग को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा पर अब हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई सुधार दिखाई देगा। हालांकि सकारात्मक पक्ष यह देखा जा सकता है कि भारत सहित विश्व के देशों में देशी पर्यटन को अवश्य बढ़ावा मिलने लगा है। लोग अपने ही देश में आसपास के स्थानों को एक्सप्लोर करने लगे हैं। वर्तमान हालात पर्यटन उद्योग के लिए बेहद चुनौती भरा है, जिसके सामान्य होने के आसार दूर-दूर तक नहीं हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर -7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व बी-142/2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 से प्रकाशित।
संपादकीय एवं संपर्क कार्यालय ए-152 सेक्टर-63, नोएडा-201301 **संपादक - आदित्य वशिष्ठ** कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई. DELHIN/2012/42452
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

संबित पात्रा ने कांग्रेस पर नक्सलवाद को पालने पोसने का आरोप लगाया

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद डॉ. संबित पात्रा ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के शासनकाल में अगर कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा द्वारा शुरू किये गये सलवा जुडूम जैसे आंदोलन को रोका ना गया होता तो भारत 2020 के पहले ही नक्सल मुक्त हो जाता।

लोकसभा में नक्सलवाद-मुक्त भारत विषय पर नियम 193 के तहत हुई अल्पकालिक चर्चा में भाग लेते हुए डॉ पात्रा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की सबसे घातक समस्या बताया था, लेकिन कांग्रेस के दूसरे धड़े ने इसे रोमांचकारी गतिविधि के रूप में दिखाने का काम किया। इसी का परिणाम था कि कांग्रेस के एक आदिवासी नेता ने नक्सलियों के खिलाफ 2005 में सलवा जुडूम आंदोलन शुरू किया जिसे भाजपा की रमन सिंह सरकार ने आगे बढ़ाया लेकिन दूसरे धड़ ने संप्रग सरकार की मूक सहमति से उच्चतम न्यायालय के माध्यम से इसे खत्म करवा दिया। उन्होंने लेखिका अरुंधती रॉय का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने नक्सलियों को गांधीवादी बंदूकधारी बताया था। भाजपा सांसद ने दंडकारण्य, पार्श्वनाथ और बूढ़ा पर्वत जैसे क्षेत्रों को 'स्वतंत्र क्षेत्र' बताते हुए कहा कि वहां भारतीय संविधान और सुरक्षा बलों का दबदबा नहीं था। उन्होंने 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले का उल्लेख किया जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 76 जवान शहीद हुए थे।

पात्रा ने उच्चतम न्यायालय में 2013 में दाखिल तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के हस्ताक्षर वाले जवाबी हलफनामे का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कहा गया था कि माओवादी शहरी नक्सलियों, अनुषांगिक संगठनों और मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के जरिए युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। हलफनामे में यह भी दर्ज था कि माओवादी सुरक्षा और विकास के अभाव वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर राजनीतिक निर्वात पैदा करते हैं। उन्होंने ओडिशा के मलकानगिरी के कलेक्टर आर विनील कृष्णन के 2011 में हुए अपहरण का जिक्र किया।

पात्रा ने कहा कि उस समय आठ माओवादियों को छोड़ा गया था, जिनमें ए पद्मा भी शामिल थीं। बाद में ए पद्मा हर्ष मंदार के संगठन 'अमन वेदिका' से जुड़ीं। उन्होंने डॉ. विनायक सेन का जिक्र करते कहा कि राजद्रोह के मामले में दोषी ठहराए जाने के बावजूद नक्सली विनायक सेन को 12वीं पंचवर्षीय योजना की स्वास्थ्य समिति में शामिल किया गया। एक बहुत बड़े पत्रकार ने उस समय लिखा था कि कांग्रेस अंदर उस समय यह भावना थी कि सैनिकों तुम संघर्ष करो, हम पता नहीं किसके साथ हैं। पात्रा ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने 2005 में सलवा जुडूम आंदोलन शुरू किया था। रमन सिंह सरकार ने पुनर्वास केंद्र बनाकर आदिवासियों को नक्सलियों से लड़ने के लिए तैयार किया। लेकिन नंदिनी सुंदर की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने 2011 में इसे समाप्त कर दिया। पात्रा ने दावा किया कि अगर सलवा जुडूम नहीं रोका जाता तो भारत 2020 तक नक्सल मुक्त हो जाता।

उन्होंने 2013 के दरभा घाटी हमले का भी जिक्र किया जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 27 लोग मारे गए थे। उन्होंने 2018 के भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले का जिक्र करते हुए रोमा विल्सन, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा और महेश राउत की गिरफ्तारी का जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी के उस समय के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने शहरी नक्सलियों का समर्थन किया। पात्रा ने कहा कि महेश राउत को 2013 में महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने पत्र लिखकर उन्हें छोड़ने की सिफारिश की थी। बाद में उन्हें पीएमआरडी फेलोशिप भी दी गई। पात्रा ने कहा कि 76 सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने पर दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में जश्न मनाया गया। यह नया भारत है जहां कांग्रेस ने आत्मसमर्पण किया है और भाजपा धुरंधर की भूमिका निभा रही है।

लोकतंत्र हमें किसी पाश्चात्य देश ने नहीं दिया यह हमारे भारत के डीएनए में है : देवनानी

भोपाल। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि लोकतंत्र हमें किसी पाश्चात्य देश ने नहीं दिया। लोकतंत्र हमारे भारत के डीएनए में है। मजबूत लोकतंत्र के लिए युवा विधायकों का सम्मेलन होना बहुत समसामयिक है। देवनानी ने यह विचार सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा में आयोजित तीन राज्यों के युवा विधायक के दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद रहे। सम्मेलन में तीन राज्यों के 45 युवा शामिल हुए हैं। राजस्थान विस अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि हम जब छात्र राजनीति में थे, तब कुलपति के सामने खड़े जाते थे। अब जनता से चुनकर आते हैं तो पद के अनुसार व्यवहार भी बदलना चाहिए। यह कोई औपचारिक सम्मेलन नहीं है। लोकतंत्र की व्याख्या करने के लिए संवाद का मंच है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में जो कठिनाई आती हैं, उनसे नई परिस्थितियों का निर्माण होता है। विरोध तार्किक प्रक्रिया होनी चाहिए। हमारा प्रतिनिधित्व सार्थक सेवा की ओर बढ़े। हम सब मिलकर नागरिकों और विधायिका के बीच संवाद करें। हमें अपने-अपने क्षेत्र में नागरिक निगरानी समितियां बनानी चाहिए। हमें मिलकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहिए।

विधानसभा सार्थक चर्चा का केंद्र है। आपकी पहचान तर्क के आधार पर बनती है। अध्ययन के आधार पर बनती है। उसके लिए आवश्यक है कि हम पूरा समय सदन में बैठने का स्वभाव बनाएं। अनुभवी लोगों के भाषण सुनें। राजस्थान के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत कर बिना किसी राजनीतिक विरासत के अपनी पहचान बनाई। उन्होंने युवाओं से राजनीति में आगे आने की अपील करते हुए कहा कि मेहनत से ही जगह बनती है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नई पीढ़ी की भागीदारी जरूरी है।

भाटी ने कहा कि आज कई जनप्रतिनिधि 'रबर स्टैंप' बनकर रह गए हैं, इसलिए पढ़े-लिखे और जागरूक नेताओं की जरूरत है ताकि 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य पूरा हो सके। राजस्थान के सादुलशहर से विधायक गुरवीर सिंह ने कहा कि हम आधारभूत संरचना की बात कर रहे हैं, लेकिन बेहतरीन निर्माण की बात नहीं करते। ओडिशा ने हॉकी को अडॉप्ट किया। इसी तरह हर राज्य को कम से कम एक खेल को अडॉप्ट करना चाहिए। मैंने अपनी विधानसभा में एक नवाचार किया। 60 पंचायतों में 35 लाइब्रेरी बनवा चुका हूं।

तमिलनाडु चुनाव 2026: नामांकन के पहले दिन ही कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा

उम्मीदवारों के अनोखे अंदाज़ ने खींचा ध्यान

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार से औपचारिक रूप से शुरू हो गई और पहले ही दिन राज्य की राजनीति पूरी तरह गरमा गई। प्रमुख राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं से लेकर स्वतंत्र उम्मीदवारों तक, सभी ने अपने-अपने तरीके से नामांकन दाखिल कर शक्ति प्रदर्शन किया और चुनावी माहौल को नई ऊर्जा दी। सबसे ज्यादा ध्यान द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर रहा, जिन्होंने चेन्नई के कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ राज्य सरकार के मंत्री पी.के. शेखर बाबू भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि स्टालिन 2011, 2016 और 2021 में लगातार इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं और इस बार चौथी बार मैदान में हैं।

नामांकन के बाद स्टालिन ने आत्मविश्वास से भरे अंदाज़ में कहा कि द्रमुक गठबंधन इस बार 200 से अधिक सीटें जीतकर भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार की योजनाओं और वादों को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। स्टालिन ने इस चुनाव को 'दिल्ली बनाम तमिलनाडु की विचारधारा' की लड़ाई बताते हुए इसे राजनीतिक से अधिक वैचारिक संघर्ष करार दिया।

तमिलगा वेत्रि कषगम (टीवीके) के नेता और अभिनेता-राजनेता विजय ने भी पेरंबूर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। उनके साथ पार्टी के महासचिव एन. आनंद और संयुक्त महासचिव सी.डी.आर. निर्मल कुमार मौजूद रहे। टीवीके के अन्य उम्मीदवारों ने भी विभिन्न सीटों से नामांकन दाखिल किया, जिससे यह साफ संकेत मिला कि पार्टी इस बार चुनाव में मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है।

नाम तमिऴर काची (एनटीके) के मुख्य समन्वयक सीमान ने कराईकुडी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। एनटीके इस बार सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, जो इसे अन्य दलों से अलग बनाता है। नामांकन के बाद सीमान ने चुनावी राजनीति में मुफ्त योजनाओं को लेकर तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि '2000, 2500 या 3000 देने के वादे करने से समाज आत्मनिर्भर नहीं बन सकता।' उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बजाय रोजगार सृजन पर जोर देने की बात कही। सीमान ने यह भी आरोप लगाया कि कोई भी दल सरकारी शराब दुकानों (टीएएसएमएसी) को बंद करने की बात नहीं कर रहा है, जो राज्य के सामाजिक ढांचे के लिए नुकसानदायक है।

उन्होंने राज्य के बढ़ते कर्ज और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे भविष्य पर गंभीर असर पड़ेगा।कराईकुडी सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। एनटीके से सीमान, अन्नाद्रमुक गठबंधन की ओर से एएमएमके उम्मीदवार थेर्पोगी पांडी और टीवीके से प्रभु मैदान में हैं। वहीं द्रमुक गठबंधन ने यह सीट कांग्रेस को दी है, हालांकि उम्मीदवार की घोषणा अभी बाकी है।पुदुकोट्टई में एनटीके उम्मीदवार इंजीनियर एझिलरसी ने नामांकन के दौरान पारंपरिक जलीकट्टू बैल के साथ रैली निकालकर सबका ध्यान आकर्षित किया।

शिवसेना ने कहा-कांग्रेस पनपने दिया नक्सलवाद तृणमूल बोली-दुनिया में दक्षिणपंथी हिंसा बढ़ी

नई दिल्ली। केन्द्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल शिवसेना ने कांग्रेस पर देश में नक्सलवाद को फैलने देने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि वामपंथ के राजनीतिक समर्थन की मजबूरी में कांग्रेस ने आदिवासियों को विकास की मुख्यधारा से दूर रख कर उन पर अत्याचारों की अनदेखी की जिससे वाम हिंसा के ₹लाल गलियारे₹ को पनपने का मौका मिला। उधर, विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि देश-दुनिया में दक्षिणपंथी हिंसा बढ़ रही है और सरकार संसद में वामपंथी हिंसा पर चर्चा करा रही है।

लोकसभा में सोमवार को नियम 193 के तहत नक्सलवाद मुक्त भारत विषय पर हुई अल्पकालीन चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। चर्चा की शुरुआत करते हुए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे देश में नक्सलवाद को फैलने का जिम्मेदार कांग्रेस को बताते हुए कहा कि नक्सलवाद पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था, अगर कांग्रेस सरकार ने समय पर समुचित कदम उठाए होते तो यह 12 राज्यों और 200 जिले नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार मजबूत नहीं बल्कि मजबूर थी। वामपंथी विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन उनकी मजबूरी थी और इसी कारण देश में नक्सलवाद बढ़ा। शिवसेना सांसद शिंदे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक साल पहले सदन में कहा था कि 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का प्रयास किया जाएगा और आज 30 मार्च को इस विषय पर चर्चा हो रही है। यह सरकार की हिम्मत है कि समय सीमा तय कर उसके पहले ही सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। जो लोग नक्सलवाद को खत्म करना असंभव बताते थे, उन्हें करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ आंदोलन चार दशकों में 12 राज्यों और 200 जिलों तक फैल गया।

कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों और पिछड़ों के लिए समय पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराईं, जिसके कारण उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ा। शिंदे ने कहा कि उस समय आदिवासियों पर अत्याचार होता था और उन्हें नक्सलवाद की आग में झोंका जाता था, लेकिन आज एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति है। यह फर्क कांग्रेस और भाजपा सरकारों के कार्यकाल का है। शिंदे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार मजबूत नहीं बल्कि मजबूर थी। वामपंथी दलों के साथ गठबंधन उनकी मजबूरी थी, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी उनकी मजबूरी थी और नीतिगत लकवा उनकी मजबूरी थी। मोदी सरकार ने अपनी मजबूत इच्छाशक्ति से रेड कॉरीडोर (लाल गलियारे) को खत्म कर देश को विकास गलियारा दिया है। औद्योगिक गलियारा, माल गलियारा, आर्थिक गलियारा और रक्षा गलियारा आज देश को नया रास्ता दिखा रहे हैं। शिंदे ने कहा कि पिछले 11 सालों में भाजपा सरकार ने कांग्रेस के पैदा किए हर बीमारी का इलाज किया है। उन्होंने गढ़चिरौली में 5 हजार युवाओं को मुख्यधारा में लाने का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि दस हजार से अधिक नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा को चुना। अकेले 2025 में 317 नक्सली मारे गए, 862 गिरफ्तार हुए और 10,900 ने आत्मसमर्पण किया। 2024 और 2025 में 28 बड़े नक्सली नेता मारे गए जिनमें केंद्रीय समिति के छह सदस्य शामिल थे। 2026 के शुरुआती तीन महीनों में ही 630 से अधिक कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में साल 2004 से 2019 के बीच राज्य में 1500 नक्सली हमले हुए जिनमें 536 लोगों की जान गई। लेकिन आज गढ़चिरौली स्टील केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने 20 हजार करोड़, 10 हजार करोड़ और एक लाख करोड़ के प्रोजेक्ट, हवाई अड्डा, रेलवे और कौशल केंद्रों को राज्य के विकास का नया केंद्र बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश से माओवाद, जातिवाद, आतंकवाद और अलगाववाद खत्म होगा और केवल राष्ट्रवाद ही रहेगा। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने इस चर्चा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा कि यह बेहद विडंबनापूर्ण है कि जब भारत समेत दुनिया दक्षिणपंथी आतंक के तहत झुलस रही है और पश्चिम एशिया का संकट गहराता जा रहा है, तब सरकार वामपंथी उग्रवाद पर चर्चा कर रही है। ऐसे समय में हम यहां नक्सलवाद पर चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा सरकार और खासकर गृह मंत्री के लिए खुद की पीठ थपथपाने का बहाना है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि नक्सलवाद की शुरुआत साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी के किसान विद्रोह से हुई थी।

यह आंदोलन चारु मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में चला। साल 2004 में पीपुल्स वॉर और माओवादी कम्युनिस्ट केंद्र का विलय होकर सीपीआई माओवादी पार्टी बनी। यह समस्या केवल कानून व्यवस्था की नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक है। आदिवासियों की जमीन का शोषण, उनका विस्थापन, प्राकृतिक संसाधनों की लूट और पिछड़े इलाकों की उपेक्षा इसकी जड़ें हैं। उन्होंने कहा कि 2019 से 2025 के बीच हत्याओं में 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि गिरफ्तारियों में 26 प्रतिशत की कमी आई है। पश्चिम बंगाल में पिछले तीन वर्षों में कोई मौत नहीं हुई है।

5 राज्यों के विस चुनावों में भारी बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार : आठवले

नई दिल्ली। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया (आरपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में आरपीआई पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में सभी सीटों पर एनडीए का समर्थन करेगी। इन सभी राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी।

रामदास आठवले ने सोमवार को कहा कि आरपीआई असम में चार सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर रही है तथा अन्य सीटों पर भाजपा व अन्य सहयोगी दलों का समर्थन करेगी। इसी प्रकार केरल में भी आरपीआई एक सीट पर अपना प्रत्याशी उतार रही है तथा बाकी सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों का सहयोग किया जाएगा। केंद्रीय राज्यमंत्री आठवले ने कहा कि आरपीआई तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है तथा बाकी सीटों पर एनडीए के समर्थन में जन समर्थन जुटाएगी। आठवले ने कहा कि आगामी 31 मार्च को पुडुचेरी तथा 5 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कोलकाता जाकर जन जन तक प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी नीतियों के विषय में बताएंगे, इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार की तिथि निर्धारित की जाएगी। केंद्रीय राज्यमंत्री आठवले ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में एनडीए की भारी जीत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में एनडीए गठबंधन सफलता का नया इतिहास रचेगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लोक कल्याण के लिए किए गए कार्य तथा पांच राज्यों में एनडीए के जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से हुआ ऐतिहासिक विकास ही भारी सफलता का आधार बनेगा।

सरकार ने दिया भरोसा- देश में पेट्रोल, डीजल एलपीजी और पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच सरकार ने देशवासियों और उद्योग जगत को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रहने का भरोसा दिया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक हालात के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। हालांकि, कुछ जगहों पर ग्राहकों के घबराहट में की जा रही खरीदारी की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने देश के ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए कई स्तरों पर त्वरित उपाय किए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोमवार को अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस समय दुनियाभर के अलग-अलग देशों के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में 28 मार्च को प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने उस

क्षेत्र में ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए हमलों की निंदा की। दोनों नेताओं ने स्वतंत्र आवागमन और शिपिंग मार्गों को खुला और सुरक्षित रखने पर भी चर्चा की। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और तेल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तरों पर कदम उठाए हैं और उठाती रहेगी। हमारी रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का स्टॉक भी पर्याप्त है। इसके अलावा घरेलू बाजार में डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की उपलब्धता बनाए रखने के लिए एक निर्यात शुल्क भी लगाई गई है। सुजाता शर्मा ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं और सीएनजी आधारित परिवहन के लिए 100 फीसदी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही ग्रिड से जुड़ी इंडस्ट्रीज के लिए 80 फीसदी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। एलपीजी के संबंध में उन्होंने कहा कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है। शर्मा ने बताया कि लगभग 95 फीसदी बुकिंग ऑनलाइन की गईं। पिछले एक हफ्ते में लगभग 2,60,005 किलोग्राम एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलेंडर बेचे गए हैं। साथ ही लगभग 41,000 टन कमर्शियल एलपीजी भी उठाई गई है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नियमित तिमाही आवंटन के अलावा अतिरिक्त 48 हजार किलोलीटर केरोसिन आवंटित किया गया है।

धर्म के आधार पर ओबीसी आरक्षण के कथित दुरुपयोग पर राज्यसभा से विपक्ष का बहिर्गमन

नई दिल्ली। विपक्षी दलों ने धर्म के आधार पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के दुरुपयोग को लेकर सोमवार को राज्यसभा में उठे सवाल पर हंगामा कर सदन से बहिर्गमन किया। सदन में शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्य के. लक्ष्मण ने धर्म के आधार पर ओबीसी आरक्षण के कथित दुरुपयोग पर मुद्दा उठाया। उन्होंने कुछ राज्यों में मुस्लिम समुदाय को मिल रहे आरक्षण की समीक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण धर्म के बजाय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर। के. लक्ष्मण ने आरोप लगाया कि तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में धर्म के आधार पर आरक्षण का गलत तरीके से लाभ दिया जा रहा है, जो असंवैधानिक है। इस पर सदन में जमकर हंगामा होने लगा। उप नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने कहा कि सदन में उठाया गया मुद्दा विभाजनकारी और पिछड़ों के आरक्षण को कमजोर करने का प्रयास है। विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बहिर्गमन किया, जिसके बाद कार्यवाही बाधित हुई।

उत्तर रेलवे

निविदा आमंत्रण सूचना

कार्य का नाम और इसकी स्थिति	73-SRDEE-G-DLI-2025-26 दिल्ली डिवीजन के डीयूके, एमटीसी और एसएमक्यूएल क्षेत्रों में स्टेशनों, सेवा भवनों, आवासीय भवनों और एलसी गेट पर रूफटॉप प्रकार के सौर संयंत्रों के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के साथ-साथ अन्य संबद्ध कार्यों का कार्य सीएएमसी के साथ पांच वर्षों के लिए किया जाएगा।
निविदा की अनुमानित लागत	रु. 4,81,02,962.00/-
कार्यालय का पता	वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियन्ता/जी, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
बयाना राशि	रु. 9,62,100.00/-
निविदा निवेदन की दिनांक व समय	21.04.2026, 16:00 बजे
निविदा खोलने की दिनांक व समय	21.04.2026, 16:00 बजे
वेबसाइट व नोटिस बोर्ड	www.ireps.gov.in वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियन्ता/जी, नई दिल्ली

1076/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

प्रदेश में 2017 से पहले पोषाहार वितरण का ठेका एक 'बड़े माफिया' के हाथों में था: योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों, खासतौर पर समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि 2017 से पहले राज्य में पोषाहार वितरण का ठेका ''एक बड़े माफिया' के हाथों में था। यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ''क्या यह उपलब्धि 2017 से पहले संभव थी? (खुद जवाब देते हुए) नहीं, क्योंकि उस समय पोषाहार वितरण का ठेका भारत का सबसे बड़ा शराब माफिया सरकार में पैसा देकर लेता था और सब कुछ वही तय करता था।''

योगी ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ''सबसे बड़ा शराब माफिया'' महिला एवं बाल विकास विभाग में भी दखल रखता था। उन्होंने कहा, ''जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने कहा कि यह तो शराब माफिया है, इसका यहां क्या काम?'' मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उस समय पोषाहार की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि वह खाने लायक ही नहीं होता था। उन्होंने कहा कि कुपोषण के कारण ही प्रदेश 'बीमारू' स्थिति में था। योगी ने सवाल किया, ''यह पाप कौन करता था, यह पाप करने वाले वही लोग हैं, जो जाति के नाम पर समाज को बांटकर समाज की सुरक्षा में भी सेंध लगाने का काम करते। बच्चों और कुपोषित माताओं के पोषाहार पर डकैती डालने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो आज नारेबाजी करके, अव्यवस्था पैदा करते।'' नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता का दावा करते हुए उन्होंने कहा, ''मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक भी कार्यकर्ता ने न सिफारिश कराई होगी और न पैसा दिया होगा। लेकिन क्या यह 2017 से पहले संभव था? (खुद जवाब देते हुए) नहीं।'' उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ''तब सिफारिश और पैसा दोनों चलते थे यानी 'पर्ची भी और खर्ची भी'।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष भी 19,424 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 3,077 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे और एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान व्यवस्था में अनियमितताओं की कोई गुंजाइश नहीं है। योगी ने कहा, ''अगर नवजात शिशु सुपोषित है और मां स्वस्थ है, तो मानकर चलिए कि भारत का भविष्य सशक्त है।''

कोविड-19 महामारी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भूमिका की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब दुनिया संकट में थी, तब ये कार्यकर्ता घर-घर जाकर कोविड प्रबंधन में अहम भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने विभाग की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जल्द ही स्पष्ट बदलाव दिखाई देगा। योगी ने कहा, ''अगर आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट हो रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं का मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए।'' उन्होंने विभाग को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, ''हम एक बड़े आयोजन के माध्यम से आपका मानदेय बढ़ाएंगे। आपको सम्मानजनक भुगतान मिलना चाहिए और न्यूनतम मानदेय की गारंटी होनी चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''पिछले नौ वर्षों में 'डबल इंजन' सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और इन प्रयासों को जमीन पर उतारने में आप सभी की अहम भूमिका है।''

योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सराहना करते हुए कहा कि वे जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा, ''आप यशोदा मैया की भूमिका निभाते हुए बच्चों के पोषण और देखभाल के साथ-साथ कुपोषण और बीमारियों के खिलाफ भी लड़ रही हैं।'' मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है और वह पिछले चार वर्षों से इस बात पर जोर दे रहे थे कि हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास स्मार्टफोन होना चाहिए। उन्होंने कहा, ''वह (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका) जो मेहनत करती हैं, वह रियल टाइम (वास्तविक समय में) डेटा समय पर नहीं मिल पाता था, जिससे रैंकिंग प्रभावित होती थी। इसलिए उन्हें स्मार्टफोन देकर प्रशिक्षित करना आवश्यक है।'' योगी ने कहा कि लखनऊ से लेकर सभी जिलों तक यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के नए डिजाइन का विमोचन भी किया गया है, जिससे उनकी भूमिका और अधिक सशक्त होगी।

> उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन के सभागार में 69,804 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन का वितरण व 18,440 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 137 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 702 आंगनवाड़ी केंद्रों एवं 71 बाल विकास परियोजना कार्यालय भवनों का शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीन से पांच वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में ही 'प्री-प्राइमरी' शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले जो 27 हजार केंद्र बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित होते थे, अब उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी और 'प्री-प्राइमरी' को छह वर्ष तक के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''इसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 'यशोदा मां' की उपाधि दी है। यह एक बड़ा सम्मान है और इसकी गरिमा बनाए रखते हुए देश के भविष्य को संवारने और मजबूत नींव तैयार करने की जिम्मेदारी आप पर है।'' कार्यक्रम के दौरान 702 आंगनबाड़ी केंद्रों और 71 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास तथा 2,468 आंगनबाड़ी केंद्रों और 69 परियोजना कार्यालयों का लोकार्पण किया गया।

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक है और इससे पहले इतने बड़े स्तर पर कार्य नहीं हुए होंगे। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल सहित कई जनप्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित रहे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 69,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन, दो लाख 'ग्रोथ मॉनिटरिंग' उपकरण तथा 18,440 कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री योगी ने पीसीएस-2024 के सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा-2024 के परिणाम घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सफल अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में सफलता को अभ्यर्थियों के परिश्रम, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम बताया।

मुख्यमंत्री ने लिखा कि पीसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त करना अभ्यर्थियों की लगन और समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने सभी चयनित युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए भरोसा जताया कि वे अपनी प्रतिभा और निष्ठा के साथ प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। प्रशासनिक सेवा केवल पद प्राप्ति नहीं, बल्कि जनसेवा का एक सशक्त माध्यम है। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ करें तथा आमजन की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि परीक्षा को पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुचिता के साथ संपन्न कराया गया, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति युवाओं का विश्वास और मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री ने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे जनसेवा को अपने आचरण का आधार बनाएं और 'नए उत्तर प्रदेश' के निर्माण में अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। पीसीएस-2024 के परिणाम के बाद प्रदेशभर में उत्साह का वातावरण है। सफल अभ्यर्थियों के घरों में खुशी का माहौल है और परिजन व शुभचिंतक उन्हें बधाई दे रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर मेहनत कर यह सफलता हासिल की है, जो अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है।

कई वाहन आपस में भिड़े, 13 लोग घायल

झांसी। जिले में सोमवार सुबह कई वाहनों के आपस में टकरा जाने के कारण कम से कम 13 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना सुबह करीब छह बजे कानपुर रोड पर बड़ागांव थाना क्षेत्र में बचावली के पास उस समय हुई जब झांसी से कानपुर जा रही रोडवेज बस सामने से लेन तोड़कर आए एक ट्रक से टकरा गई। इसी दौरान पीछे से आ रही एक मारुति कार भी बस से जा टकराई। थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि इस हादसे में रोडवेज बस की परिचालक रिचा साहू और कार सवार तीन लोग सहित 13 लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश की जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार, सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है।

अवैध निर्माण पर चला बुल्डोजर, तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त

सीतापुर। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में कल रविवार को कैप्टन मनोज पांडे चौक का चौड़ीकरण के लिए बाधा बन रहे एक मंदिर को हटाने के बाद प्रशासन ने आज एक अवैध मस्जिद को ढहा दिया।

जनपद के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नयागांव बेहटी गांव में सोमवार तड़के जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मस्जिद के ढांचे को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के अनुसार यह निर्माण सरकारी तालाब और कब्रिस्तान की भूमि पर किया गया था। प्रशासन की पूरी टीम रात करीब 3 बजे ही मौके पर पहुंच गई थी। सुबह लगभग 5 बजे से बुलडोजर की मदद से ध्वस्तीकरण शुरू हुआ, जो करीब 8 बजे तक चला। इस दौरान मस्जिद के अधिकांश हिस्से को गिरा दिया गया, जबकि मलबा हटाने का कार्य जारी है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौके पर एडीएम नीतीश कुमार, एएसपी आलोक सिंह, सीओ लहरपुर और एसडीएम लहरपुर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा 2 प्लाटून पीएसी, 18 थाना प्रभारी, 35 सब इंस्पेक्टर और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन के अनुसार कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध या अप्रिय घटना नहीं हुई। प्रशासन का कहना है कि करीब 12 वर्ष पूर्व लगभग डेढ़ बीघा जमीन पर यह निर्माण किया गया था, जिसे ग्राम सभा की शिकायत के बाद चिन्हित किया गया।

> एडीएम नीतीश कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

मामले में 18 दिसंबर 2025 को तहसीलदार कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत संबंधित पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ प्रशासन की निगरानी जारी है।

वाराणसी हवाई अड्डे पर विमान का दरवाजा खोलने की कोशिश करने पर युवक गिरफ्तार

वाराणसी। वाराणसी के बाबतपुर में स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बेंगलुरु से आए इंडिगो के विमान का दरवाजा खोलने की कोशिश करने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

फूलपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान अदनान के रूप में हुई है, जो शनिवार रात बेंगलुरु से इंडिगो की ऊड़ान 6ई 185 में सवार हुआ था। विमानन कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, यात्रा शुरू होते ही युवक ने विमान का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन चालक दल के सदस्यों ने उसे रोका और बिठा दिया।

वाराणसी में उतरने के बाद, वह फिर से दरवाजे के पास पहुंचा, जिसके बाद चालक दल ने हस्तक्षेप करके उसे रोक दिया। उन्होंने बताया कि इंडिगो प्रबंधन की ओर से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसे बाबतपुर हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया।

अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि यह उसकी पहली हवाई यात्रा थी और वह घबराया हुआ था, जिसके कारण उसने ऐसा किया होगा। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

गैस संकट पर कांग्रेस ने निकाली सिलेंडर की अर्थी, जताया आक्रोश

कानपुर। शहर में बढ़ती गैस की किल्लत और आम जनता की परेशानियों के विरोध में सोमवार को कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। अध्यक्ष पवन गुप्ता और एआईसीसी सदस्य जे.पी. पाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया से ममता गैस एजेंसी तक पदयात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से गैस सिलेंडर की अर्थी निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया और सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया।

पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाए और जनता की परेशानियों को उजागर करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की। मानवीय पहल के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाइन में खड़े लोगों को ठंडा पानी वितरित किया और उनकी समस्याएं सुनी। महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि सरकार की लापरवाही और अव्यवस्थित आपूर्ति व्यवस्था आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रही है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि गैस आपूर्ति तुरंत सुचारू की जाए और जनता को राहत प्रदान की जाए। एआईसीसी सदस्य जेपी पाल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता के साथ खड़ी रही है और आगे भी उनके हक के लिए संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस बड़े आंदोलन को बाध्य होगी। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से आग्रह किया कि गैस वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए और आम जनता के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में तीन लोगों की मौत, दो अन्य घायल

हरदोई। हरदोई जिले के सवायजपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने बताया कि बंथला गांव निवासी दीपक (20), गोविंद (20), लंकुश (40) तथा ईश्वर दयाल (15) एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर रविवार को सवायजपुर की ओर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि इसी दौरान गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर खितौली गांव के पास तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि हादसे में मोटरसाइकिल सवार सभी लोग और कार सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। एएसपी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने लंकुश, गोविंद और दीपक को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल ईश्वर दयाल को जिला मेडिकल कॉलेज भेजा गया है जबकि एक अन्य घायल का उपचार किया जा रहा है। सिंह ने बताया कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।

ग्रामीणों ने गांव का नाम बदलने की चर्चाओं पर जताई आपत्ति, कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

उरई। उत्तर प्रदेश के उरई में जिला जालौन कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को ग्राम चमारी के दर्जनों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन के बिना सहमति के गांव का नाम बदलने की कोशिश किए जाने के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की और प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए।

उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से गांव का नाम परिवर्तन किए जाने की चर्चाएं ज़ोर पकड़ रही हैं, जिससे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उनके गांव की एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है, जिससे कोई भी समझौता अस्वीकार्य है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव का नाम हमारी पहचान है। बिना हमारी सहमति के नाम बदलने का कोई भी प्रयास सामूहिक विरोध का सामना करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा इस मामले में स्थानीय लोगों की राय नहीं ली गई, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस दौरान ग्रामीणों ने सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार को एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में गांव का नाम न बदलने की मांग को प्रमुखता से रखा गया। साथ ही, चेतावनी दी गई कि यदि प्रशासन ने एकतरफा फैसला लिया, तो आंदोलन को और तीव्र कर दिया जाएगा। किसी भी निर्णय से पहले ग्रामीणों की आम सभा बुलाकर सहमति लेना अनिवार्य है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि फिलहाल इस मामले में कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांगें प्रशासन के संज्ञान में हैं।

किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों की राय ली जाएगी और पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों का धरना समाप्त किया। इस दौरान रविकांत, प्रताप सिंह, बबलू प्रदीप कुमार, शशिकांत ठाकुर, मनीष मुन्ना, ऋतक, राम अवतार, रितेश कुमार मौजूद रहे।

आईआईटी कानपुर और यूआईईटी के बीच हुआ एमओयू, शोध व नवाचार को बढ़ावा

कानपुर। तकनीकी शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आईआईटी कानपुर और यूआईईटी, सीएसजेएम विश्वविद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सोमवार को हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत दोनों संस्थानों के छात्रों को शोध व नवाचार में बढ़ावा मिलेगा।

यह समझौता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के डीन अकादमिक प्रो. अशोक डे एवं सीएसजेएम विश्वविद्यालय के डीन अकादमिक प्रो. बृष्टि मित्रा द्वारा संपन्न किया गया। इस अवसर पर यूआईईटी के निदेशक डॉ. आलोक कुमार उपस्थित रहे। इस समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग को सुदृढ़ करना है। एमओयू के अंतर्गत छात्र-छात्राओं एवं शोधार्थियों को अनेक अवसर प्राप्त होंगे। यूआईईटी के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र आईआईटी कानपुर के प्रतिष्ठित समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम (एसआरआईपी) में भाग ले सकेंगे।

समझौते के तहत यूआईईटी छात्रों को आईआईटी कानपुर में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, दोनों संस्थानों के संकाय सदस्य एवं शोधार्थी आपसी सहमति से एक-दूसरे के संस्थानों में निर्धारित अवधि तक शोध कार्य कर सकेंगे। यह साझेदारी विभिन्न तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को गति देगी।

पुलिस ने कब्र से किशोरी का शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम भेजा

सीतापुर। जिले के रामकोट थाना क्षेत्र में जिलधिकारी के आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोमवार को एक किशोरी के शव को कब्र से बाहर निकालकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी पीयूष सिंह ने बताया कि शिवपाल की बेटी दामिनी ने 28 फरवरी को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए शव को दफना दिया था। लेकिन इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब मृतक किशोरी की मां अनीता ने सात मार्च को थाना रामकोट में नामजद तहरीर देकर हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपित अम्बुज समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस ने जिलाधिकारी से किशोरी का शव कब्र से खुदवाकर पोस्टमार्टम की अनुमति मांगी थी। आदेश के बाद पुलिस ने सोमवार को मजिस्ट्रेट की निगरानी में किशोरी के शव को कब्र से बाहर निकालकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अपनी पसंद से शादी करना किसी अन्य के सम्मान का मुद्दा नहीं, वयस्कों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य : हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा कि कोई भी व्यक्ति बालिगों द्वारा अपनी पसंद से की गई शादी को सम्मान का मुद्दा नहीं बना सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में राज्य का दायित्व है कि वह दम्पति के जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति की रक्षा करे, भले ही खतरा उनके अपने परिवार से ही क्यों न हो।

जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह टिप्पणी याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें अलीगढ़ के एक दम्पति ने अपनी सुरक्षा की मांग की है। दोनों ने अपनी मर्जी से आर्य समाज मंदिर में विवाह किया था और उनके पास वैध विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र भी था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि महिला के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ हैं और उन्होंने झूठा आपराधिक मामला दर्ज करा दिया। दम्पति ने संयुक्त हलफनामा दाखिल कर यह भी आशंका जताई कि उन्हें ''ऑनर किलिंग'' का खतरा है।

अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए कहा, ''किसी बालिग के निजी निर्णय को सम्मान का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता।'' हाईकोर्ट ने सम्बंधित पक्ष को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही अंतरिम राहत देते हुए अदालत ने आदेश दिया कि इस मामले में दम्पति को गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने महिला के परिवार के सदस्यों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि वे दम्पति को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाएं। उनके वैवाहिक घर में प्रवेश न करें और न ही सीधे या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्पर्क करें। इसके अलावा, अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि वह सुनिश्चित करें कि दम्पति को किसी भी प्रकार का खतरा न हो। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 08 अप्रैल को करेगी।

तीन दिन से लापता किशोर का शव नहर किनारे झाड़ियों में मिला, हत्या का संदेह

कुशीनगर। कुशीनगर जिले के हाटा थाना क्षेत्र में तीन दिन से लापता एक किशोर का शव घर से करीब दो किलोमीटर दूर नहर किनारे झाड़ियों से बरामद किया गया। पुलिस ने हत्या का संदेह जताया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, गोपालपुर विरैचा गांव में अपने ननिहाल में रह रहा राजवीर यादव (12) शुक्रवार अपराह्न करीब तीन बजे सामान खरीदने दुकान पर गया था और काफी देर तक वापस न आने पर परिजनों ने उसके मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद मिला।

उसने बताया कि किशोर के लापता होने पर उसी रात करीब आठ बजे उसके मामा आदित्य की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई और तलाश शुरू की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे गांव से लगभग दो किलोमीटर दूर रधिया-देवरिया मार्ग के पास बाजार से लौट रहे कुछ लोगों ने नहर किनारे झाड़ियों में एक शव देखा जिसकी पहचान बाद में राजवीर के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि उसके गले पर काले निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या का संदेह पैदा हो गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। उन्होंने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से रामकोला के कतरौल निवासी राजवीर के पिता प्रमोद यादव रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में हैं। प्रमोद की पत्नी रीना अपने दोनों बेटों के साथ मायके में रहती है।

गुजरात और पंजाब के पहले मुकाबले में खुद को साबित करने उतरेंगे गिल और अय्यर

मुल्लांपुर। भारतीय टीम से बाहर टी20 बल्लेबाज शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जब इंडियन प्रीमियर लीग के पहले मैच में क्रमशः गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की अगुवाई करेंगे तो उनका इरादा खुद को साबित करने का भी होगा । भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान गिल को टी20 टीम का उपकप्तान बनाया गया था लेकिन बाद में विश्व कप टीम से बाहर कर दिया गया । उनकी जगह संजू सैमसन को चुना गया था जिनका भारत की खिताबी जीत में अहम योगदान रहा ।

वर्ष 2023 के बाद से आईपीएल में गिल से ज्यादा रन सिर्फ विराट कोहली ने बनाये हैं लेकिन अब फोकस निरंतरता की बजाय स्ट्राइक रेट पर है । गिल का टी20 कैरियर का स्ट्राइक रेट 138 है लेकिन पिछले साल उन्होंने 155 की स्ट्राइक रेट से रन बनाये । अब बल्लेबाजी कोच के तौर पर मैथ्यू हेडन स्टाफ का हिस्सा है लिहाजा गिल की छक्के मारने के कौशल और बल्लेबाजी पर नजर रखी जायेगी । हार्दिक पंड्या के जाने के बाद से गिल ने कप्तानी का जिम्मा भी बखूबी संभाला है । अपने पदार्पण वर्ष 2022 में आईपीएल खिताब जीतने वाली गुजरात टाइटंस पिछले साल तीसरे स्थान पर रही । एक बार फिर टीम काफी संतुलित लग रही है । सलामी बल्लेबाज गिल और साइ सुदर्शन सबसे बड़ी ताकत हैं । सुदर्शन ने पिछले सत्र में सर्वाधिक 759 रन बनाये थे । वह पसली के फ्रेक्चर से उबरकर लौट रहे हैं लेकिन घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है ।

गुजरात के पास विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र जैसे विकल्प भी हैं जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 160 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से रन बनाये थे । पंजाब किंग्स के लिये एक बार फिर श्रेयस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा जो तीन अलग अलग टीमों को आईपीएल फाइनल तक ले जा चुके हैं ।उनकी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स 2020 में और पंजाब पिछले सत्र में फाइनल तक पहुंची जबकि केकेआर ने 2024 में खिताब जीता था । लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद श्रेयस को भारतीय टी20 टीम में जगह नहीं मिली और भारत के लिये आखिरी टी20 उन्होंने दिसंबर 2023 में खेला था । पिछले सत्र में उन्होंने 175 से अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 604 रन बनाये थे । वह एशिया कप और टी20 विश्व कप टीम में जगह नहीं बना सके थे । पंजाब की ताकत उसके भारतीय क्रिकेटरों में है जिनमें सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य शामिल है । सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हालांकि उनका बल्ला खामोश रहा था ।मध्यक्रम में निहाल वढेरा, शशांक सिंह और सूर्यांश शेडगे हैं जिनका सामना राशिद खान की अगुवाई में बेहतरीन स्पिन आक्रमण से होगा ।

इस प्रकार है दोनों टीम

- **पंजाब किंग्स :** श्रेयस अय्यर (कप्तान), निहाल वढेरा, विष्णु विनोद, हरनूर पन्नू , पाइला अविनाश, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, हरप्रीत बरार , मार्को यानसेन, अजमतुल्लाह उमरजइ, प्रियांश आर्य, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, मिच ओवेन, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विशाख विजयकुमार, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद ।
- **गुजरात टाइटंस :** शुभमन गिल (कप्तान), साइ सुदर्शन, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, टॉम बेंटोन, ग्लेन फिलिप्स, निशांत सिंधू, वॉशिंगटन सुंदर , मोहम्मद अरशद खान, साइ किशोर, जयंत यादव, जैसन होल्डर, राहुल तेवतिया, शाहरूख खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुतार, गुरनूर सिंह बरार, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, ल्यूक वुड, कुलवंत हेजरोलिया , राशिद खान ।

मैच का समय : शाम 7 . 30 से ।

कारूआना, प्रज्ञानानंदा कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में पहले दौर के बाद शीर्ष पर

पाफोस (साइप्रस)। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरूआत नीदरलैंड के अनीश गिरि को हराकर की और वह अमेरिकी ग्रैंडमास्टर फेबियानो कारूआना तथा उजबेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं ।

पहले दौर में विश्व कप चैम्पियन सिंदारोव ने रूस के आंद्रेइ एसिपेंको को हराया जबकि कारूआना ने अमेरिका के ही हिकारू नकामूरा का मात दी । आठ खिलाड़ियों के दोहरे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में जर्मनी के मथियास ब्लूबाम और चीन के वेइ यि के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा । महिला वर्ग में भारतीय ग्रैंडमास्टर और महिला विश्व कप चैम्पियन दिव्या देशमुख ने यूक्रेन की अन्ना मुजिचुक से ड्रॉ खेला जो कोनेरू हम्पी की जगह खेल रहीं हैं। वहीं आर वैशाली ने कजाखस्तान की बिबिसारा असायुबायेवा से ड्रॉ खेला। रूस की अलेक्जेंड्रा गोरियाश्किना ने हमवतन कैटरीना लागनो से ड्रॉ खेला जबकि चीन की झू जिनेर और तान झोंग्यी के बीच मुकाबला भी बराबरी पर छूटा ।

कैंडिडेट्स टूर्नामेंट ओपन और महिला वर्ग में खेला जाता है जिससे अगले विश्व चैम्पियनशिप मुकाबले के चैलेंजर का निर्धारण होगा । इस समय डी गुकेश और चीन की जू वेंजुन विश्व चैम्पियन हैं ।

फखर जमां ने गेंद से छेड़खानी के आरोपों को खारिज किया

लाहौर। पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज फखर जमां ने लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच पाकिस्तान सुपर लीग के मैच के दौरान गेंद से छेड़खानी के आरोपों को खारिज किया है। पैतीस बरस के फखर को मैच रैफरी रोशन महानामा ने पीएसएल की खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिये आचार संहिता की धारा 2 . 14 के तहत लेवल तीन के अपराध का दोषी पाया था। यह आरोप कराची किंग्स की पारी के आखिरी ओवर से पहले का है जब उन्हें जीत के लिये 14 रन की जरूरत थी। फखर को हारिस रऊफ और लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से बात करते देखा गया। इसके बाद अंपायर फैसल अफरीदी ने गेंद मांगी और उसे देखने के बाद पाया कि इससे छेड़छाड़ की गई है। मैच रैफरी अगले 48 घंटे में फिर सुनवाई के बाद फैसला सुनायेंगे।

मियामी ओपन 2026: यानिक सिनर ने जीरी लेहेका को हराकर जीता खिताब

मियामी। मियामी ओपन के बारिश से प्रभावित फाइनल में इटली के स्टार खिलाड़ी यानिक सिनर ने रविवार रात चेक गणराज्य के जीरी लेहेका को 6-4, 6-4 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ सिनर बिना एक भी सेट गंवाए 'सनशाइन डबल' पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

विश्व नंबर दो सिनर ने मुकाबले में अपने पहले सर्विस पर 92 प्रतिशत अंक जीते और पूरे मैच के दौरान मिले तीनों ब्रेक प्वाइंट बचाए। इस जीत के साथ उन्होंने मास्टर्स 1000 मुकाबलों में बिना सेट गंवाए अपनी जीत की श्रृंखला को 17 तक पहुंचा दिया। मुकाबले के बाद सिनर ने कहा, "हमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। अब घर लौटने को लेकर भी उत्साहित हूं। पहली बार सनशाइन डबल हासिल करना मेरे लिए अविश्वसनीय है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव हो पाएगा।" बारिश के कारण मुकाबला लगभग 90 मिनट देर से शुरू हुआ। इसके बावजूद सिनर ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले सेट में जल्दी 3-1 की बढ़त बनाई और मजबूत सर्विस के दम पर सेट अपने नाम किया। दूसरे सेट की शुरुआत में फिर बारिश के चलते खेल रोकना पड़ा, लेकिन वापसी के बाद सिनर ने अपना दबदबा कायम रखा। लेहेका, जो अपने करियर का पहला मास्टर्स 1000 फाइनल खेल रहे थे, ने दूसरे सेट में कड़ा मुकाबला दिया। उन्होंने कई ब्रेक प्वाइंट बचाए और एक समय 4-3 की बढ़त भी बना ली, लेकिन सिनर ने निर्णायक क्षणों में बेहतर खेल दिखाते हुए वापसी की। सिनर ने दूसरे सेट में अपने छठे ब्रेक प्वाइंट पर सफलता हासिल कर 5-4 की बढ़त बनाई और फिर अपनी सर्विस पर मैच जीत लिया।

गौरतलब है कि सिनर 2017 में रोजर फेडरर के बाद पहले खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने इंडियन वेल्स और मियामी ओपन खिताब लगातार जीते हैं। इस उपलब्धि को 'सनशाइन डबल' कहा जाता है। इस खास उपलब्धि के साथ सिनर ने नोवाक जोकोविच, आंद्रे आगासी, पीट सैम्प्रास, माइकल चांग और जिम कूरियर जैसे महान खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

शीतल देवी को विश्व तीरंदाजी ने 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज' चुना

लुसाने। भारत की शीतल देवी को विश्व तीरंदाजी ने वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज चुना है जिनकी असाधारण उपलब्धियों में ऐतिहासिक विश्व चैम्पियनशिप खिताब शामिल है । जम्मू कश्मीर की 19 वर्ष की शीतल देवी विश्व पैरा चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भुजाहीन तीरंदाज बनी । उन्होंने पिछले साल दक्षिण कोरिया के ग्वांग्जू में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में खिताब जीता था । शीतल भुजायें नहीं होने के बावजूद अपने पैर और कंधे का इस्तेमाल करके तीरंदाजी करती हैं। वह विश्व चैम्पियनशिप में महिला टीम में रजत और मिश्रित टीम में कांस्य भी जीत चुकी है । विश्व तीरंदाजी ने कहा कि भारत की शीतल देवी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज चुना गया है जिन्होंने पिछले साल बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विश्व खिताब समेत कई उपलब्धियां हासिल की। शीतल ने पेरिस पैरालम्पिक में मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता था। वह एशियाई पैरा खेल 2022 और 2023 एशियाई चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत रजत जीत चुकी है । शीतल ने सोमवार को एक्स पर लिखा ,' दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाजों के साथ नामांकन मिलना और अब विश्व तीरंदाजी द्वारा सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज चुना जाना । इस सफर में जो भी मिला उसके लिये मेरा दिल कृतज्ञता और भावनाओं से भरा हुआ है । धन्यवाद ।''

हॉकी इंडिया ने की 31 सदस्यीय सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की घोषणा

2026 के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारियों के तहत आयोजित होगा शिविर

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया ने सोमवार को भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए 1 से 9 अप्रैल 2026 तक सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की घोषणा की है। यह शिविर आगामी व्यस्त अंतरराष्ट्रीय सत्र की तैयारियों के मद्देनजर आयोजित किया जा रहा है। भारतीय टीम हाल ही में एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 क्वालीफायर) में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने के साथ-साथ एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है।

ऐसे में यह शिविर टीम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। नए मुख्य कोच सजोर्ड मरिजन के मार्गदर्शन में इस शिविर का मुख्य उद्देश्य टीम संयोजन तैयार करना, फिटनेस स्तर में सुधार लाना और खेल की रणनीति को और धार देना होगा। भारतीय टीम जून में एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप 2026 में हिस्सा लेगी, जिसके बाद अगस्त में विश्व कप और फिर 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान में होने वाले एशियाई खेल 2026 में भाग लेगी।

शिविर को लेकर कोच ने कहा, "यह शिविर हमारे लिए एक अहम कदम है। हमारा ध्यान निरंतरता सुधारने, टीम संरचना को मजबूत करने और खिलाड़ियों को शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार करने पर रहेगा। हमारा लक्ष्य ऐसी टीम बनाना है जो बड़े मुकाबलों में दबाव झेलकर बेहतर प्रदर्शन कर सके।"

31 सदस्यीय दल

- गोलकीपरः सविता, माधुरी किंडो, बिछू देवी खरीबाम, बंसारी सोलंकी।
- डिफेंडर्सः निक्की प्रधान, इशिका चौधरी, ज्योति सिंह, लालथंथलुआंगी, ज्योति, उदिता, शिल्पी डबास।
- मिडफील्डरः सुशीला चानू पुखरंबम, मनीषा चौहान, वैशणवी विट्ठल फाल्के, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, सलीमा टेटे (कप्तान), नेहा, इशिका।
- फॉरवर्डः दीपिका सोरेंग, रुतजा दादासो पिसाल, बलजीत कौर, नवनीत कौर, दीपिका, अन्नू, ब्यूटी डुंगडुंग, हीना बानो, सोनम, लालरेमसियामी, मुमताज खान, संगीता कुमारी (रिहेब)

वोल्टास को सीमा शुल्क विभाग का 23.52 करोड़ रुपये का नोटिस

नई दिल्ली। टाटा समूह की कंपनी वोल्टास लिमिटेड को आयातित वस्तुओं के कथित गलत वर्गीकरण के मामले में सीमा शुल्क अधिकारियों से 23.52 करोड़ रुपये का मांग नोटिस मिला है। इसमें शुल्क और जुर्माना दोनों शामिल हैं। वोल्टास ने कहा कि वह इस आदेश का विश्लेषण कर रही है और इस मामले में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेसटैट) के समक्ष अपील दायर करने सहित उचित कानूनी कदम उठाएगी। एयर-कंडीशनर बनाने वाली कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि यह मामला 14 जून, 2019 से 21 जुलाई, 2022 की अवधि के दौरान कुछ आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण से संबंधित है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत, यदि विभाग को लगता है कि कर की यह कमी जानबूझकर या जानकारी छिपाने के कारण हुई है, तो वह 'बकाया कर' के अलावा जुर्माना भी लगाता है। इस मामले में जुर्माना 12.76 करोड़ रुपये मूल कर देयता 10.76 करोड़ से भी अधिक है, जो मामले की गंभीरता को दर्शाता है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि इस जुर्माने के कारण उसकी वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

डिजाइन, 'सिक्स सिग्मा' गुणवत्ता मानक पूरे नहीं होने पर ईसीएमएस के तहत भुगतान रोकेंगे : वैष्णव

नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि यदि लाभार्थी उत्पाद डिजाइन प्रौद्योगिकी में निवेश नहीं करते और 'सिक्स सिग्मा' मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो सरकार इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जा विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) के तहत भुगतान रोक सकती है।

ईसीएमएस के तहत 7,104 करोड़ रुपये के नए निवेश से जुड़े 29 प्रस्तावों को मंजूरी देने के बाद मंत्री ने आगाह किया कि जो लाभार्थी उत्पाद डिजाइन प्रौद्योगिकी में निवेश नहीं करेंगे, उन्हें योजना से बाहर किया जा सकता है। वैष्णव ने कहा, '' यदि उद्योग की ओर से अपेक्षित प्रयास नहीं किए जाते हैं तो मैं आगे किसी भी भुगतान या नई मंजूरी को रोकने के लिए तैयार हूं।'' मंत्री ने उच्च गुणवत्ता एवं आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निर्धारित एकीकृत दृष्टिकोण का पालन नहीं करने पर उद्योग संगठन इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) और उसकी सदस्य कंपनियों की आलोचना भी की। उन्होंने कहा, '' समय के साथ जो कंपनियां डिजाइन में निवेश नहीं करेंगी, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें बाहर किया जाए। मैं यह बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं क्योंकि यह हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम हमेशा 'राष्ट्र प्रथम' में विश्वास करते हैं।'' वैष्णव ने कहा कि देश को इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, कलपुर्जा डिजाइन और मशीन डिजाइन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है।

मंत्री ने उद्योग को 15 दिन की समयसीमा दी है, जिसके भीतर कंपनियों को सरकार को यह बताना होगा कि उन्होंने उत्पाद डिजाइन, 'सिक्स सिग्मा' मानक, प्रतिभा विकास और स्थानीय आपूर्ति (सोर्सिंग) जैसे प्रमुख मुद्दों पर क्या कदम उठाए हैं। 'सिक्स सिग्मा' एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसका उद्देश्य उत्पादन में त्रुटियों को न्यूनतम करना और लगभग पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। वैष्णव ने कहा कि ईसीएमएस के तहत अब तक स्वीकृत सभी 75 आवेदनों को 15 दिन के भीतर अपनी कार्ययोजना साझा करनी होगी।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया एक अप्रैल से कुछ मॉडल की कीमत दो प्रतिशत तक बढ़ाएगी

नई दिल्ली। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया कच्चे माल की बढ़ती लागत के असर को आंशिक रूप से कम करने के लिए एक अप्रैल, 2026 से अपने कुछ मॉडल की कीमतों में दो प्रतिशत तक की वृद्धि करेगी।

कंपनी सोमवार को बयान में कहा कि यह कीमत वृद्धि उसके मुख्य खंड के मॉडल पर लागू होगी और एमजी सिलेक्ट चैनल के माध्यम से बेचे जाने वाले प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनों एमजी एम9 और साइबरस्टर पर लागू नहीं होगी। बयान के अनुसार, कि यह मूल्य संशोधन लगातार बढ़ रही कच्चे माल की लागत के प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

कंपनी वर्तमान में अपने एमजी खंड के तहत पारंपरिक इंजन (आईसीई) और इलेक्ट्रिक वाहनों की एक श्रृंखला बेचती है।

देश में बैंक एक सख्त कानूनी और नियामक ढांचे के तहत काम करते हैं : सीतारमण

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि देश में बैंक अपने ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानूनी और नियामक ढांचे के तहत काम करते हैं। उन्होंने यह बात प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कही। वित्त मंत्री ने बताया कि 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) व्यवस्था और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत बैंकों के लिए ग्राहकों की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि बैंक केवल आवश्यकता के आधार पर ही ग्राहकों का डेटा एकत्र करते हैं और जरूरत पड़ने पर ही इसे अधिकृत एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है। सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंकिंग क्षेत्र में डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पांच प्रमुख कानून लागू हैं। इनमें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अधिनियम शामिल हैं, जिनका पालन सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ग्राहक को धोखाधड़ी या बिना अनुमति के डेटा साझा किए जाने की शिकायत होती है, तो वह भारतीय रिज़र्व बैंक या संबंधित प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।

ऐसे मामलों में संबंधित संस्थाएं जांच कर आवश्यक कार्रवाई करती हैं। वित्त मंत्री ने सदन को यह भी आश्वस्त किया कि सरकार बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है और इस दिशा में लगातार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

डब्ल्यूटीओ वार्ता समाप्त, ई-कॉमर्स पर शुल्क से जुड़ी रोक बढ़ाने पर कोई सहमति नहीं

नई दिल्ली। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का चार दिवसीय 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी-14) सोमवार को कैमरून के याउंडे में समाप्त हो गया, लेकिन इसमें ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क पर रोक की अवधि को बढ़ाने के विवादास्पद मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सका। हालांकि, इस दौरान जिनेवा में प्रमुख लंबित मुद्दों पर काम जारी रखने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है।

कैमरून के व्यापार मंत्री एवं एमसी-14 के अध्यक्ष ल्यूक मैग्लोयर मबार्गा अटांगा ने 'एक्स' पोस्ट कहा कि विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी-14) आज सुबह संपन्न हुआ, जिसमें जिनेवा में प्रमुख लंबित मुद्दों पर काम जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई गई। उन्होंने कहा कि चार दिवसीय बैठक के दौरान मंत्रियों ने बातचीत के विभिन्न क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को सुलझाने के लिए काम किया। अटांगा ने चर्चाओं को आगे बढ़ाने वाले मंत्रियों के साथ-साथ बैठक में मौजूद सभी मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों को उनके 'अथक परिश्रम' के लिए धन्यवाद दिया।

ल्यूक मैग्लोयर मबार्गा अटांगा ने बताया कि चार दिन की बैठक में व्यापार मंत्रियों ने कई मुद्दों को निपटाने की कोशिश की, लेकिन समय की कमी के कारण कुछ लंबित मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। इनमें ई-कॉमर्स पर डब्ल्यूटीओ की कार्य प्रक्रिया, 'इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन' पर सीमा शुल्क वसूलने पर लगी वर्तमान रोक को जारी रखने और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (टीआरआईपीएस) से जुड़ी शिकायतों का समाधान जैसे विषय सम्मिलित थे। अब इन विषयों पर चर्चा संगठन के मुख्यालय जिनेवा में होगी।

केंद्र ने 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 60 दिन के लिए केरोसिन के वितरण की अनुमति दी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई और रोशनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिट्टी के तेल (केरोसिन) के अस्थायी वितरण को मंजूरी दे दी है। हालांकि, ये राज्य पहले केरोसिन-मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। यह 60 दिन की आपातकालीन व्यवस्था रसोई गैस (एलपीजी) पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए की गई है। यह निर्णय पश्चिम एशिया में पिछले एक माह से जारी युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति, विशेषकर रसोई गैस (एलपीजी) में बाधा आने के बाद लिया गया है।

भारत अपनी रसोई गैस की लगभग 60 प्रतिशत जरूरत को आयात के जरिये पूरा करता है, जिनमें से 85-90 प्रतिशत गैस खाड़ी देशों से आती है। युद्ध के कारण इसकी आपूर्ति में रुकावट आई है, जिससे होटल और रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए गैस की आपूर्ति कम करनी पड़ी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 29 मार्च की अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत अस्थायी छूट प्रदान की है ताकि 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत केरोसिन का वितरण सुचारू रूप से किया जा सके। अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक जिले में अधिकतम दो नामित सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनी (ओएमसी) के पेट्रोल पंप को 5,000 लीटर तक केरोसिन रखने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। इन पेट्रोल पंप पर केरोसिन भरने के लिए एजेंट और डीलर को लाइसेंस लेने से छूट दी गई है, जबकि पहले से लाइसेंसधारी टैंकर वाहनों को भी इसके लिए अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये छूट कड़ाई से सुरक्षा मानकों और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा जारी संचालन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने के शर्त पर दी गई है। केरोसिन के भंडारण, भराई और वितरण का पूरा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए और इसे जिला प्रशासन तथा पीईएसओ द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा और 60 दिन तक या अगले आदेश तक वैध रहेगा। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, केरोसिन का उपयोग खाना पकाने और रोशनी के लिए किया जाएगा। इसे उन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अस्थायी रूप से फिर से उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्हें पहले 'पीडीएस एसकेओ (केरोसिन-मुक्त)' घोषित किया गया था। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं।

'ग्लोबल गरबा' पर ट्विंकल खन्ना का कटाक्ष

अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर किया मजाकिया वार

मुंबई। ट्विंकल खन्ना ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर मजाकिया पोस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप और कूटनीति पर तंज कसते हुए 'ग्लोबल गरबा' की दिलचस्प तुलना की। बॉलीवुड अभिनेत्री और लेखिका ट्विंकल खन्ना एक बार फिर अपने चुटीले अंदाज को लेकर चर्चा में आ गई हैं। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद भी ट्विंकल अपने बेबाक और व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए लगातार सुर्खियां बटोरती रहती हैं। इस बार उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और नेताओं के व्यवहार पर एक दिलचस्प टिप्पणी की है, जो तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल, अपने हालिया पोस्ट में ट्विंकल खन्ना ने वैश्विक कूटनीति पर तंज कसते हुए इसे "ग्लोबल गरबा" से जोड़ दिया। उन्होंने एक वीडियो का जिक्र किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जापान के प्रधानमंत्री के सामने पर्ल हार्बर को लेकर टिप्पणी करते नजर आते हैं। इस संदर्भ को आधार बनाते हुए ट्विंकल ने वर्तमान वैश्विक राजनीति की शैली पर कटाक्ष किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि पहले कूटनीति काफी संतुलित और गंभीर हुआ करती थी, लेकिन अब यह बदलती नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने भारत की विदेश नीति की तुलना गुजराती गरबा से करते हुए कहा कि यह एक ऐसा संतुलन है, जिसमें सभी के साथ तालमेल बनाकर चला जाता है, बिना किसी को नाराज किए। आपको बता दें कि ट्विंकल खन्ना ने व्यंग्यात्मक अंदाज में यह भी कहा कि आज के दौर में वैश्विक राजनीति एक तरह का "डांस" बन चुकी है, जहां हर नेता अलग-अलग देशों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस शैली को भारतीय दृष्टिकोण से सराहते हुए कहा कि संतुलन बनाए रखना ही असली कला है। इसके अलावा, उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में अपनी जीवनशैली और डाइट को भी इस चर्चा में शामिल किया। डोनाल्ड ट्रंप की डाइट और एनर्जी का जिक्र करते हुए उन्होंने मजाक में कहा कि शायद वह गलत सलाह का पालन कर रही हैं, क्योंकि उनके पास उतनी ऊर्जा नहीं है जितनी ट्रंप में बताई जाती है। ट्विंकल खन्ना का यह पोस्ट एक बार फिर साबित करता है कि वह गंभीर मुद्दों को भी हास्य और व्यंग्य के जरिए प्रस्तुत करने में माहिर हैं। उनके इस अंदाज को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस पोस्ट पर जमकर प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं।

40 की उम्र में दूसरी बार मां बनीं

सोनम कपूर

"सोनम कपूर के घर आई खुशियों की बहार, दूसरे बेटे को दिया जन्म

मुम्बई। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा के घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। सोनम कपूर ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। इस खुशखबरी के बाद कपूर और आहूजा परिवार में जश्न का माहौल है। सोशल मीडिया पर फैंस और फिल्मी सितारे इस कपल को लगातार बधाइयां दे रहे हैं। सोनम और आनंद ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इस खुशखबरी को शेयर किया। उन्होंने एक भावुक नोट में लिखा कि बहुत कृतज्ञता और प्यार से भरे दिल के साथ हम अपने बेटे के आगमन की घोषणा कर रहे हैं। हमारा परिवार अब और भी खूबसूरत हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका बड़ा बेटा वायु आहूजा अपने छोटे भाई के आने से बेहद खुश है। इस खास मौके पर परणीति चोपड़ा, करीना कपूर और हुमा कुरैशी समेत कई बॉलीवुड सितारों ने कपल को शुभकामनाएं दीं और नन्हे मेहमान पर प्यार लुटाया। सोशल मीडिया पर फैंस भी इस खुशी में शामिल होते नजर आए और लगातार बधाई संदेश भेज रहे हैं। गौरतलब है कि सोनम और आनंद की पहली मुलाकात साल 2015 में हुई थी, जिसके बाद दोनों ने 2018 में शादी रचाई। साल 2022 में उनके पहले बेटे वायु का जन्म हुआ था। अब दूसरे बेटे के आगमन के साथ यह परिवार चार सदस्यों का हो गया है। काम के मोर्चे पर सोनम कपूर को आखिरी बार फिल्म 'ब्लाइंड' में देखा गया था।

'धुरंधर 2' का जलवा देश से विदेश तक

विवेक अग्निहोत्री ने अमेरिका में देख की जमकर तारीफ

मुम्बई। रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर 2' का खुमार अब देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ फिल्म को दर्शकों और फिल्मी हस्तियों से भी जबरदस्त सराहना मिल रही है। हाल ही में फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने अमेरिका में इस फिल्म को देखने के बाद इसकी खुलकर तारीफ की है। विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि वह कैलिफोर्निया के ग्रामीण इलाके में थे, लेकिन 'धुरंधर 2' देखने के लिए खास तौर पर लॉस एंजिल्स पहुंचे। उन्होंने फिल्म की सराहना करते हुए लिखा, शाबाश, बहुत बढ़िया, एक बार फिर शानदार। उन्होंने निर्देशक आदित्य धर के काम की भी जमकर तारीफ की और कहा कि फिल्म अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अग्निहोत्री ने फिल्म की तकनीकी टीम की भी सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से सिनेमेटोग्राफर विकास नौलखा और प्रोडक्शन डिजाइनर सैनीस जोहराय के काम को सराहा और कहा कि इन दोनों ने फिल्म को एक अलग ऊंचाई दी है। साथ ही उन्होंने आदित्य धर को सलाह देते हुए कहा कि वह अपने रास्ते पर कायम रहें, लेकिन फिल्मी दुनिया के माहौल को लेकर सतर्क भी रहें। गौरतलब है कि 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तब से लगातार शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने अब तक 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जो इसकी जबरदस्त लोकप्रियता का प्रमाण है। फिल्म का यह प्रदर्शन इसे साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल कर रहा है।